EXPLANATION

INDIAN ECONOMY -2- 31 MARCH, 2019

1.A

- A Non-Banking Financial Company (NBFC) is a company registered under the Companies Act, 1956 engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares/stocks/bonds/debentures/securities issued by Government or local authority or other marketable securities of a like nature, leasing, hire-purchase, insurance business, chit business but does not include any institution whose principal business is that of agriculture activity, industrial activity, purchase or sale of any goods (other than securities) or providing any services and sale/purchase/construction of immovable property. A non-banking institution which is a company and has principal business of receiving deposits under any scheme or arrangement in one lump sum or in installments by way of contributions or in any other manner, is also a non-banking financial company (Residuary non-banking company).
- In terms of Section 45-IA of the RBI Act, 1934, no Non-banking Financial company can commence or carry on business of a non-banking financial institution without obtaining a certificate of registration from the Bank.
- NBFCs lend and make investments and hence their activities are akin to that of banks; however there are a few differences as given below:

i. NBFC cannot accept demand deposits;

ii. NBFCs do not form part of the payment and settlement system and cannot issue cheques drawn on itself; **Hence, statement 1 is correct.**

iii. deposit insurance facility of deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation is not available to depositors of NBFCs, unlike in case of banks.

iv. NBFC do not maintain CRR. **Hence, statement 2 is correct.**

v. The Priority Sector Lending rules are not applicable on NBFCs. **Hence, statement 3 is not correct.**

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC), कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पंजीकृत कंपनी है। यह ऋण और अग्रिम, सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए शेयरों/स्टॉक्स/बांडों/डिबेंचर/प्रतिभूतियों या समान प्रकृति की अन्य व्यापारिक प्रतिभूतियों के अधिग्रहण, पट्टा, किराया-खरीद, बीमा व्यवसाय, चिट व्यवसाय आदि व्यवसाय से संबंधित है। परन्तु इसमें कोई भी ऐसी संस्था, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, किसी भी सामान की खरीद या बिक्री (प्रतिभूतियों के अलावा) है या कोई सेवा प्रदान करना तथा अचल संपत्ति की बिक्री/खरीद/निर्माण करना है, सम्मिलित नहीं है। एक गैर-बैंकिंग संस्था, जो एक कंपनी हो और जिसका प्रमुख व्यवसाय किसी भी योजना या व्यवस्था के तहत एकमुश्त या किश्तों के माध्यम से, योगदान अथवा किसी अन्य तरीके से जमा प्राप्त करना हो, भी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (अवशिष्ट गैर- बैंकिंग कंपनी) है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के संदर्भ में, कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी RBI से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में व्यवसाय या कार्य संचालन नहीं कर सकती।
- NBFCs उधार देते हैं और निवेश करते हैं इसलिए उनकी गतिविधियां बैंकों के समान होती हैं; हालांकि इनमें नीचे दिए गए कुछ अंतर भी हैं:

1. NBFC मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती है;
2. NBFCs भुगतान और निपटान प्रणाली का भाग नहीं है तथा आहरित चेक जारी नहीं कर सकती हैं; **इसलिए, कथन 1 सही है।**
3. बैंकों की भांति, जमा बीमा (deposit Insurance) एवं क्रेडिट गारंटी निगम (Credit Guarantee Corporation) की सुविधाएँ NBFCs के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है।
4. NBFC को नकद आरक्षित अनुपात (CRR) बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है। **इसलिए, कथन 2 सही है।**
5. NBFCs पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण (PSL) से सम्बंधित नियम लागू नहीं होते हैं। **इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।**

2.C

Statement 1 is correct: An IFSC caters to customers outside the jurisdiction of the domestic economy. **Such centres deal with flows of finance, financial products and services across borders. London, New York and Singapore can be counted as global financial centres.** Many emerging IFSCs around the world, such as Shanghai and Dubai, are aspiring to play a global role in the years to come. An expert panel headed by former World Bank economist Percy Mistry submitted a report on making Mumbai an international financial centre in 2007

IFSC can provide

- Fund-raising services for individuals, corporations and governments
- Asset management and global portfolio diversification undertaken by pension funds, insurance companies and mutual funds
- Wealth management

- Global tax management and cross-border tax liability optimization, which provides a business opportunity for financial intermediaries, accountants and law firms.
- Global and regional corporate treasury management operations that involve fund-raising, liquidity investment and management and asset-liability matching
- Risk management operations such as insurance and reinsurance
- Merger and acquisition activities among trans-national corporations.

Statement 2 is not correct: The SEZ Act, 2005 allows setting up an IFSC in an SEZ or as an SEZ after approval from the central government.

Statement 3 is correct: Gujarat International Finance Tec-City Co. Ltd has been developed as the country's first international financial services centre (IFSC).

कथन 1 सही है: इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विस सेंटर (IFSC) घरेलू अर्थव्यवस्था के क्षेत्राधिकार के बाहर ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार ये सीमा पारीय वित्त प्रवाह, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति में सहायता करते हैं। लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर को वैश्विक वित्तीय केंद्र रूप में माना जा सकता है। विश्व भर के अनेक उभरते हुए IFSC, जैसे शंघाई और दुबई, आगामी वर्षों में वैश्विक भूमिका निभाने के इच्छुक हैं। विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री पर्सी मिस्त्री की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने 2007 में मुंबई को एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने संबंधी रिपोर्ट सौंपी थी।

IFSC द्वारा प्रदत्त लाभ हैं:

- व्यक्तियों, निगमों और सरकारों के लिए धन जुटाने संबंधी सेवाएं,
- पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड द्वारा आरंभ किए गए वैश्विक पोर्टफोलियो विविधीकरण और संपत्ति का प्रबंधन
- धन प्रबंधन
- वैश्विक कर प्रबंधन और सीमा पार कर देयता अनुकूलन, जो वित्तीय मध्यस्थों, एकाउंटेंट और लॉ फर्मों के लिए व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है।
- वैश्विक और क्षेत्रीय कॉरपोरेट ट्रेजरी प्रबंधन संबंधी संचालन, जिसमें धन-जुटाना, तरलता का निवेश और प्रबंधन एवं परिसंपत्ति-दायित्व अनुकूलन शामिल है
- जोखिम प्रबंधन का परिचालन जैसे बीमा एवं पुनर्बीमा
- अंतर्राष्ट्रीय निगमों के मध्य विलय और अधिग्रहण संबंधी गतिविधियां

कथन 2 सही नहीं है: SEZ अधिनियम, 2005 केंद्र सरकार से अनुमोदन के बाद IFSC को SEZ में या SEZ के समान, स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करता है।

कथन 3 सही है: गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कंपनी लिमिटेड को देश में प्रथम अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विस सेंटर (IFSC) के रूप में विकसित किया गया है।

3.C

- **Statement 1 is correct:** Development Impact Bonds (DIBs), like Social Impact Bonds (SIBs), are results-based contracts in which private investors provide pre-financing for social programmes and public sector agencies pay back investors their principal plus a return if, and only if, these programmes succeed in delivering social outcomes. Unlike SIBs, DIBs involve donor agencies, either as full or joint funders of outcomes. Because repayment to investors is contingent upon the achievement of specified social outcomes, DIBs are not "bonds" in the conventional sense.
- **Statement 2 is correct:** A new Development Impact Bond i.e. The Utkrisht Impact Bond was developed by USAID, Merck for Mothers, the UBS Optimus Foundation, PSI, Palladium, and HLFPPT. It is the world's first health impact bond with an aim to reduce the number of mother and baby deaths by improving the quality of maternal care in Rajasthan's health infrastructure. The Utkrisht Impact Bond will enable financial assistance for 440 small healthcare organisations to improve the quality of maternal and child care in Rajasthan's hospitals and adhere to the government's quality standards.
- **कथन 1 सही है:** डेवलपमेंट इम्पैक्ट बांड (DIBs), सोशल इम्पैक्ट बांड (SIBs) के समान, परिणाम-आधारित अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट्स) होते हैं। इन बांड में निजी निवेशकों द्वारा सामाजिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए पूर्व-वित्तपोषण प्रदान किया जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा केवल उन सामाजिक कार्यक्रमों के सफल (सोशल आउटकम देने की स्थिति में) होने पर ही ऐसे निवेशकों को उनका मूलधन ब्याज सहित वापस किया जाता है। SIBs के विपरीत, DIBs में दाता एजेंसियों को पूर्ण या संयुक्त दाता के रूप में, सम्मिलित किया जाता है। चूंकि निवेशकों के निवेश का पुनर्भुगतान विशिष्ट सामाजिक परिणामों की उपलब्धि पर निर्भर होता है, इसलिए औपचारिक रूप से DIBs को 'बांड' नहीं माना जा सकता।
- **कथन 2 सही है:** एक नये डेवलपमेंट इम्पेक्ट बांड अर्थात् उत्कृष्ट इम्पेक्ट बांड को USAID, मर्क फॉर मदर (Merck for Mothers), USB ऑप्टिमस फाउंडेशन, PSI, पैलेडियम (Palladium), और HLFPPT द्वारा विकसित किया गया है। यह विश्व का प्रथम हेल्थ इम्पैक्ट बांड है, जिसका उद्देश्य राजस्थान की स्वास्थ्य से संबंधी अवसंरचना में सुधार करके शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर को कम करना है। उत्कृष्ट इम्पैक्ट बांड के माध्यम से राजस्थान के अस्पतालों में माताओं एवं शिशुओं की देखभाल और सरकारी मानकों को पूरा करने के लिये 440 छोटे हेल्थकेयर संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध की जा रही है।

4.D

5.D

The Reserve Bank of India (RBI) regulates and supervises Public Sector and Private Sector Banks. The powers of RBI are wide-ranging and comprehensive to deal with various situations that may emerge in all banks, irrespective of ownership i.e. the Public Sector and the Private Sector owned Banks.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। RBI की शक्तियां विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए व्यापक हैं, जो सभी बैंकों के समक्ष उत्पन्न होती हैं, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाले बैंक हों।

6.C

The Reserve Bank of India has allowed tokenisation of debit, credit and prepaid card transactions to enhance the safety of the digital payments ecosystem in the country. Tokenization will replace card details with a code, called a "token," which will be specifically for the card, the token requestor and the device being used to pay. Instead of the card's details, the token will act as the card at point of sale (POS) terminals and quick response (QR) code payment systems. The goal of the process is to improve the safety and security of payments.

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड लेनदेन के टोकनाईज़ेशन की अनुमति दी है। टोकनाईज़ेशन, कार्ड विवरण को एक कोड के साथ बदल देगा, जिसे "टोकन" कहा जाता है, जो विशेष रूप से कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और भुगतान करने के लिए उपयोग किए जा रहे डिवाइस के लिए होगा। कार्ड के विवरण के बजाय, टोकन प्वाइंट ऑफ सेल (POS) टर्मिनलों और त्वरित प्रतिक्रिया (QR) कोड भुगतान प्रणालियों में कार्ड के रूप में कार्य करेगा। प्रक्रिया का लक्ष्य भुगतानों की सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार करना है।

7.A

- **Insolvency and Bankruptcy Code, aims to consolidate the laws relating to insolvency of companies and limited liability entities (including limited liability partnerships and other entities with limited liability), unlimited liability partnerships and individuals, presently contained in a number of legislations, into a single legislation**. Such consolidation will provide for a greater clarity in law and facilitate the application of consistent and coherent provisions to different stakeholders affected by business failure or inability to pay debt.
- The salient features of the law are as follows:

i. Clear, coherent and speedy process for early identification of financial distress and resolution of companies and limited liability entities if the underlying business is found to be viable.

ii. **Debt Recovery Tribunal and National Company Law Tribunal to act as Adjudicating Authority and deal with the cases related to insolvency, liquidation and bankruptcy process in respect of individuals and unlimited partnership firms and in respect of companies and limited liabilities entities respectively.**

iii. Establishment of an Insolvency and Bankruptcy Board of India to exercise regulatory oversight over insolvency professionals, insolvency professional agencies and information utilities.

iv. Insolvency professionals would handle the commercial aspects of insolvency resolution process. Insolvency professional agencies will develop professional standards, code of ethics and be first level regulator for insolvency professionals members leading to development of a competitive industry for such professionals.

v. Information utilities would collect, collate, authenticate and disseminate financial information to be used in insolvency, liquidation and bankruptcy proceedings.

vi. **Enabling provisions to deal with cross border insolvency.**

वर्तमान में कंपनियों एवं सीमित दायित्व वाली इकाइयों (सीमित दायित्व भागीदारी एवं अन्य संस्थाओं सहित), असीमित दायित्व भागीदारी तथा व्यक्तियों के दिवालियापन से संबंधित अनेक कानून विद्यमान है। दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड) का उद्देश्य इन सभी कानूनों को एक ही कानून के अंतर्गत समेकित करना है। इस प्रकार का समेकन, कानून में अधिक स्पष्टता लाने एवं व्यापार विफलता या कर्ज चुकाने में असमर्थ हितधारकों हेतु अनुकूल एवं सुसंगत प्रावधानों को कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान करेगा।

इस कानून की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- यदि अंतर्निहित व्यवसाय को व्यवहार्य पाया जाता है, तो वित्तीय संकट और कंपनियों एवं सीमित दायित्व संस्थाओं की शीघ्र पहचान हेतु स्पष्ट, सुसंगत एवं त्वरित प्रक्रिया को अपनाकर विश्लेषित किया जाएगा।
- **ऋण वसूली न्यायाधिकरण एवं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को निर्णायक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने तथा कंपनियों एवं सीमित उत्तरदायित्व संस्थाओं के सम्बन्ध में व्यक्तियों तथा असीमित साझेदारी व्यवसायों के दिवालियापन, ऋणशोधन तथा दिवालियापन की प्रक्रिया से संबंधित मामलों का निपटान करना।**
- इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, एजेंसियों तथा इनफॉर्मेशन यूटिलिटीज के नियामक निरीक्षण हेतु **इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया** की स्थापना।
- इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, दिवालिया समाधान प्रक्रिया संबंधी व्यावसायिक पहलुओं का निपटान करेंगे। इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एजेंसियों द्वारा इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए पेशेवर मानदंडों, आचार संहिता के निर्माण के साथ-साथ प्राथमिक स्तर के विनियामक के रूप में कार्य किया जाएगा। जिसके परिणामस्वरूप इस प्रकार के प्रोफेशनल्स के लिए एक प्रतिस्पर्धी उद्योग का विकास होगा।

- **इनफॉर्मेशन यूटिलिटीज** दिवाला, ऋणशोधन एवं दिवालियापन की प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली संबंधित आर्थिक जानकारियों को एकत्रित, तुलना, प्रमाणीकृत एवं प्रसारित करेगी।

यह सीमापार (क्रॉस बॉर्डर) दिवालियेपन से निपटने हेतु विभिन्न प्रावधानों को सक्षम बनता है।

8.C

Statement 1 is not correct. The inflow of foreign capital leads to appreciation of the rupee, while the outflow would lead to depricaition of the rupee. When the foreign institutional investors (FIIs) bring their capital into India, they need to convert these currencies into rupees, to be able to buy stocks. Hence, they need to sell their currencies to buy rupees. When this happens, the demand for the rupee goes up and pushes up its value against the foreign currency.

Statement 2 is correct: The current account is the balance of trade between a country and its trading partners, reflecting all payments between countries for goods, services, interest and dividends. A deficit in the current account shows that the country is spending more on foreign trade than it is earning, and that it is borrowing capital from foreign sources to make up the deficit. In other words, the country requires more foreign currency than it receives through sales of exports, and it supplies more of its own currency than foreigners demand for its products. The excess demand for foreign currency lowers the country's exchange rate until domestic goods and services are cheap enough for foreigners, and foreign assets are too expensive to generate sales for domestic interests. Hence, higher current account deficit can lead to depreciation of rupee while lower current deficit can lead to appreciation of rupee.

Statment 3 is not correct: As a general rule, a country with a consistently lower inflation rate exhibits a rising currency value, as its purchasing power increases relative to other currencies. Those countries with higher inflation typically see depreciation in their currency in relation to the currencies of their trading partners.

- **कथन 1 सही नहीं है।** विदेशी पूंजी के अंतर्वाह के कारण रुपए का अधिमूल्यन होता है जबकि बहिर्वाह के कारण रुपए का अवमूल्यन होता है। जब विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) भारत में अपना पूंजी निवेश करते हैं तो उन्हें स्टॉक क्रय हेतु इन मुद्राओं को रूपये में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, उन्हें रुपये को क्रय के लिए अपनी मुद्राओं का विक्रय करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में रुपये की मांग बढ़ जाती है और विदेशी मुद्रा की तुलना में इसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है।
- **कथन 2 सही है:** चालू खाता, एक देश और उसके व्यापारिक भागीदारों के मध्य व्यापार संतुलन होता है जो वस्तुओं, सेवाओं, ब्याज और लाभांशों के लिए देशों के मध्य सभी भुगतानों को दर्शाता है। चालू खाता घाटा, किसी देश द्वारा विदेशों को विक्रय से प्राप्त धन की तुलना में विदेशों को किए गए अधिक भुगतान को दर्शाता है, और इस घाटे की पूर्ति हेतु विदेशी स्रोतों से पूंजी उधार ली जाती है। अन्य शब्दों में, देश को निर्यातों की बिक्री से प्राप्त मुद्रा की अपेक्षा अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है और यह विदेशियों द्वारा की गयी उत्पादों की मांग की तुलना में स्वयं की मुद्रा की अधिक आपूर्ति करता है। विदेशी मुद्रा के लिए अतिरिक्त मांग देश की विनिमय दर को तब तक कम करती है जब तक घरेलू सामान और सेवाएं विदेशियों के लिए पर्याप्त रूप से सस्ती न हो जाएँ और विदेशी संपत्तियाँ घरेलू बाजार द्वारा खरीदे जाने हेतु अत्यधिक महंगी न हो जाएँ। इसलिए, चालू खाता घाटे में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप रुपए का अवमूल्यन हो सकता है, जबकि निम्न चालू घाटे के कारण रुपये का अधिमूल्यन हो सकता है।
- **कथन 3 सही नहीं है:** एक सामान्य नियम के अनुसार, निरंतर निम्न मुद्रास्फीति दर वाला देश बढ़ते हुए मुद्रा मान को दर्शाता है क्योंकि इसकी क्रय शक्ति अन्य मुद्राओं की अपेक्षा बढ़ जाती है। उच्च मुद्रास्फीति वाले देशों की मुद्रा में सामान्यतः उनके व्यापार भागीदारों की मुद्राओं के संबंध में अवमूल्यन होता है।

9.A

- The **Gini coefficient is an important tool for analyzing income or wealth distribution within a country or region**, but it should not be mistaken for an absolute measurement of income or wealth.
- **The Gini index is often represented graphically through the Lorenz curve, which shows income (or wealth) distribution by plotting the population percentile by income on the horizontal axis and cumulative income on the vertical axis.**The coefficient ranges from 0 (or 0%) to 1 (or 100%), with 0 representing perfect equality and 1 representing perfect inequality.
- किसी देश या क्षेत्र में **आय या धन वितरण के विश्लेषण हेतु गिनी गुणांक एक महत्वपूर्ण तरीका है** लेकिन इसको आय या धन के निरपेक्ष माप का पैमाना नहीं माना जाना चाहिए।
- **गिनी इंडेक्स प्रायः लोरेन्ज वक्र के माध्यम से रेखाचित्र रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें क्षैतिज अक्ष पर आय के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर संचयी आय अंकित करते हुए आय के वितरण को दर्शाया जाता है।** गुणांक 0 (या 0%) से लेकर 1 (या 100%) के मध्य मापन करता है, 0 पूर्ण समानता तथा 1 पूर्ण असमानता को दर्शाता है।

10.C

- **Statement 1 is correct:** Gender Budgeting is a powerful tool for achieving gender mainstreaming so as to ensure that benefits of development reach women as much as men. It is not an accounting exercise but an ongoing process of keeping a gender perspective in policy/ programme formulation, its implementation and review. GB entails dissection of the Government budgets to establish its gender differential impacts and to ensure that gender commitments are translated in to budgetary commitments.
- **Statement 2 is correct:** Government of India introduced the first gender budget statement in 2005-06. Gender Budgeting can be applied to the entire National Budget or to the Budget of a State or Local Body. It can be applied to a selected Department or just one

programme, which may be an existing programme or a new programme. It can be applied on the expenditure side or the revenue side. It can be applied to new or existing Legislation.

- Several State Governments have implemented Gender Budgeting with significant success. States such as Karnataka, Kerala, Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and many others have taken significant steps to institutionalise Gender Budgeting to address gender gaps.

- **कथन 1 सही है:** लैंगिक समानता को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए लैंगिक (जेंडर) बजट एक प्रभावी उपकरण है, जिससे महिलाओं को भी पुरुषों के समान विकास का लाभ मिल सके। यह एक लेखा अभ्यास नहीं है, अपितु नीति/कार्यक्रम के निर्माण और उनके कार्यान्वयन एवं समीक्षा में लैंगिक दृष्टिकोण को अपनाने की एक सतत प्रक्रिया है। लैंगिक बजट, सरकार के बजट विश्लेषण में लिंग विभेदकारी प्रभावों को स्थापित करने और लैंगिक प्रतिबद्धताओं को बजटीय प्रतिबद्धताओं में परिवर्तित किए जाने को सुनिश्चित करता है।
- **कथन 2 सही है:** भारत सरकार द्वारा 2005-06 में प्रथम लैंगिक बजट विवरण प्रस्तुत किया गया। जेंडर बजट को समग्र राष्ट्रीय बजट या किसी राज्य या स्थानीय निकाय के बजट पर लागू किया जा सकता है। यह एक चयनित विभाग या सिर्फ एक योजना पर लागू किया जा सकता है, जो वर्तमान में प्रचलित अथवा नई योजना भी हो सकती है। यह व्यय पक्ष या राजस्व पक्ष पर लागू किया जा सकता है। इसे नए या वर्तमान कानून पर भी लागू किया जा सकता है।
- कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण सफलता के साथ जेंडर बजट को लागू किया है। कर्नाटक, केरल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य कई राज्यों ने लैंगिक अंतराल को कम करने हेतु लैंगिक बजट को संस्थागत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

11.A

The International Energy Agency's (IEA) flagship publication World Energy Outlook (WEO), widely regarded as the gold standard of energy analysis, provides strategic insight on what today's policy and investment decisions mean for long-term trends. Based on rigorous modelling across different scenarios, the WEO projections are used by public and private sector stakeholders as a framework for policy-making, planning and investment decisions, and to identify pathways to a sustainable energy future.

वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक (WEO) का प्रकाशन **इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी** (IEA) द्वारा किया जाता है। **WEO को** व्यापक रूप से ऊर्जा विश्लेषण के मानक के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह इस सम्बन्ध में रणनीतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि वर्तमान नीति और निवेश निर्णयों के दीर्घकालीन रुझान क्या होंगे। WEO अनुमान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों द्वारा नीति निर्माण, योजना और निवेश निर्णय के लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में उपयोग किये जाते हैं। इसके साथ ही इन अनुमानों का उपयोग भविष्य में सतत ऊर्जा की राह की पहचान करने में किया जाता है।

12.D

- Convertibility is the ease with which a country's currency can be converted into gold or another currency. It indicates the extent to which the regulations allow inflow and outflow of capital to and from the country. **Capital account convertibility allows freedom to convert local financial assets into foreign financial assets and vice-versa.** As of today, one can still bring in foreign capital or take out local money for these purposes, but there are ceilings imposed by the government that need approvals.
- The expected outcomes of full Capital Account Convertibility are:

i. **Increased liquidity in financial markets**: Full capital account convertibility opens up the country's markets to global players, including investors, businesses and trade partners. This allows easy access to capital for different businesses and sectors, positively impacting a nation's economy. There are numerous restrictions on foreigners who want to invest in India, especially in debt, or in industries by way of FDI. If there is full capital account convertibility, money will freely move in and out of India. **Hence, statement 2 is correct.**

ii. **Easy access to foreign capital:** Local businesses can benefit from easy access to foreign loans at comparatively lower costs (low interest rates). Indian companies currently have to take the ADR/GDR route to list in foreign exchanges. Since India does not have full capital account convertibility, there are certain caps on the ECB framework. After full convertibility, they will be able to directly raise equity capital from overseas markets. **Hence, statement 3 is correct.**

iii. **High volatility:** Amid a lack of suitable regulatory control and rates subject to open markets with large number of global market participants, high levels of volatility, devaluation or inflation in forex rates may happen, challenging the country's economy. **Hence, statement 1 is correct.**

- परिवर्तनीयता एक ऐसी सुगम प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी देश की मुद्रा को स्वर्ण या अन्य मुद्राओं में परिवर्तित किया जा सकता है। यह इंगित करता है कि नियमों के अंतर्गत किसी देश में और देश से बाहर पूंजी के अंतप्रर्वाह एवं बहिप्रर्वाह की अनुमति किस सीमा तक है। **पूंजी खाते में परिवर्तनीयता स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में और साथ ही विदेशी वित्तीय परिसम्पत्तियों को स्थानीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान करती है। वर्तमान में, इसमें सभी उद्देश्यों के लिए पूंजी के सरल एवं अप्रतिबंधित प्रवाह की भी अनुमति होती है।** परन्तु सरकार द्वारा सीमाएं निर्धारित की गयी हैं, जिनके लिए अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता के अपेक्षित परिणाम इस प्रकार हैं:

I. **वित्तीय बाजारों में तरलता में वृद्धि:** पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता ने देश के बाजारों को निवेशकों, व्यवसायों और व्यापार भागीदारों सहित वैश्विक अभिकर्ताओं के लिए खोल दिया है। यह विभिन्न व्यवसायों और क्षेत्रों को पूंजी तक सुगम पहुंच की अनुमति प्रदान करता है। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। भारत में निवेश के इच्छुक विदेशियों पर कई प्रतिबंध आरोपित किये गए हैं, विशेषकर उन पर जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से ऋण में या

उद्योगों में निवेश करना चाहते। यदि भारत में पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता हो तो भारत में धन का आंतरिक और वाह्य प्रवाह स्वतंत्र रूप से होगा। इसलिए, **कथन 2 सही है।**

1. **विदेशी पूंजी तक सुगम पहुंच:** स्थानीय व्यवसायों को अपेक्षाकृत कम लागत (कम ब्याज दरों) पर विदेशी ऋणों तक सुगम पहुंच से लाभ प्राप्त हो सकता है। भारतीय कंपनियों को वर्तमान में विदेशी एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के लिए ADR/GDR रूट को अपनाना होता है। चूंकि भारत में पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं है, इसलिए ECB ढांचे पर कुछ सीमाएँ निर्धारित की गयी हैं। पूर्ण परिवर्तनीयता के बाद, वे सीधे विदेशी बाजारों से इक्विटी पूंजी जुटाने में सक्षम होंगे। **इसलिए, कथन 3 सही है।**

2. **उच्च अस्थिरता:** उचित विनियामक नियंत्रण और दरों के अभाव में, खुले बाजार में बड़ी संख्या में वैश्विक प्रतिभागियों की उपस्थिति की दशा में, रुपये में उच्च अस्थिरता, अवमूल्यन या विदेशी विनिमय दर में वृद्धि हो सकती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौती उत्पन्न हो सकती है। **इसलिए, कथन 1 सही है।**

13.D

- **Micro Units Development Refinance Agency (MUDRA) Bank is a refinance institution for micro-finance institutions. MUDRA is conceived not only as a refinance institution and but also as a regulator for the micro finance institutions (MFIs).**
- **It has been setup as a wholly owned subsidiary of SIDBI.**
- The MUDRA Bank is primarily be responsible for –

i. Laying down policy guidelines for micro/small enterprise financing business.
ii. Registration of MFI entities.
iii. Regulation of MFI entities.
iv. Accreditation /rating of MFI entities.
v. Laying down responsible financing practices to ward off indebtedness and ensure proper client protection principles and methods of recovery.
vi. Development of standardized set of covenants governing last mile lending to micro/small enterprises.
vii. Promoting right technology solutions for the last mile.
viii. Formulating and running a Credit Guarantee scheme for providing guarantees to the loans which are being extended to micro enterprises.
ix. Creating a good architecture of Last Mile Credit Delivery to micro businesses under the scheme of Pradhan Mantri Mudra Yojana.

In lending, MUDRA gives priority to enterprises set up by the under-privileged sections of the society particularly those from the scheduled caste / tribe (SC/ST) groups, first generation entrepreneurs and existing small businesses.

- ***माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा)* बैंक सूक्ष्म-वित्तीय संस्थानों (MFIs) के लिए एक पुनर्वित्तीयन संस्थान है। मुद्रा को न केवल एक पुनर्वित्तीयन संस्थान के रूप में बल्कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (MFIs) के नियामक के रूप में भी माना जाता है ।**
- **इसकी स्थापना SIDBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गयी है।**
- मुद्रा बैंक मुख्यतः निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है -

1. सूक्ष्म/लघु उद्यम वित्तपोषण व्यवसाय हेतु नीतिगत दिशा-निर्देशों को निर्धारित करना
2. MFI संस्थाओं का पंजीकरण
3. MFI संस्थाओं का विनियमन
4. MFI संस्थाओं का प्रत्यायन / रेटिंग
5. ऋणग्रस्तता की समाप्ति और उचित ग्राहक सुरक्षा सिद्धांतों एवं वसूली के तरीकों को सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार वित्तपोषण तरीकों को निर्धारित करना।
6. सूक्ष्म/लघु उद्यमों को लास्ट माइल लैंडिंग उपलब्ध कराने वाले नियमों के मानकीकृत समुच्चय का विकास।
7. लास्ट माइल के लिए सही प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देना
8. लघु उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों को गारंटी प्रदान करने हेतु एक क्रेडिट गारंटी योजना का निर्माण और उसका संचालन करना ।
9. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म व्यवसायों के लिए लास्ट माइल क्रेडिट डिलिवरी की एक बेहतर संरचना विकसित करना। ऋण देने में, मुद्रा ने समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति / जनजाति (SC/ST) समूहों, प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों और मौजूदा छोटे व्यवसायों से स्थापित उद्यमों को प्राथमिकता दी गई है।

14.D

There are different forms of money supply – reserve money, narrow money, broad money etc. But the most important indicator of all these is reserve money. It is also called as high powered money, base money and central bank money. All these name suggests that reserve money represents the base level for money supply or it is the high powered component of money supply

Reserve money = Currency in Circulation + Bankers' Deposits with RBI + 'Other' Deposits with RBI

- **Option 1 is correct:** Among these components, the most important one is currency in circulation. It includes notes in circulation, rupee coins and small coins.

- **Option 2 is correct:** Bankers' Deposits with the RBI represent balances maintained by banks in the current account with the Reserve Bank mainly for maintaining Cash Reserve Ratio (CRR) and as working funds for clearing adjustments.
- **Option 3 is correct:** Other Deposits with the Reserve Bank for the purpose of monetary compilation includes deposits from foreign central banks, multilateral institutions, financial institutions etc.

मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न रूप हैं - आरक्षित मुद्रा, संकीर्ण मुद्रा, व्यापक मुद्रा आदि। लेकिन इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण सूचक आरक्षित मुद्रा है। इसे उच्च शक्ति मुद्रा,आधार मुद्रा और केंद्रीय बैंक मुद्रा भी कहा जाता है। ये सभी नाम दर्शाते हैं कि आरक्षित मुद्रा, मुद्रा आपूर्ति हेतु आधार स्तर का कार्य करती है अथवा यह मुद्रा की आपूर्ति का उच्च शक्ति घटक है।

आरक्षित मुद्रा = चलन में मुद्रा/प्रचलित मुद्रा + RBI के साथ बैंकरों की जमाएँ + RBI के साथ अन्य जमाएँ

- **विकल्प 1 सही है:** इन घटकों में, सबसे महत्वपूर्ण प्रचलित मुद्रा मानी जाती है। इसमें चलन में शामिल रुपया सिक्के, छोटे सिक्के और नोट्स शामिल होते हैं।
- **विकल्प 2 सही है:** RBI के पास बैंकों की जमाओं में मुख्यतः नकद आरक्षित अनुपात (CRR) बनाए रखने हेतु रिजर्व बैंक के चालू खाते में बैंकों की जमाएँ एवं समाशोधन के समायोजन हेतु कार्यशील पूँजी शामिल होता है।
- **विकल्प 3 सही है:** मौद्रिक संकलन के उद्देश्य हेतु रिज़र्व बैंक के साथ अन्य जमाओं में विदेशी केंद्रीय बैंकों, बहुपक्षीय संस्थानों, वित्तीय संस्थानों आदि से सम्बंधित जमायें शामिल होती हैं।

15.A

16.D

- The Government has revised the base year of All-India Wholesale Price Index (WPI) from 2004-05 to 2011-12. The revision of the base year of the macroeconomic indicators is a regular exercise to capture structural changes in the economy and to improve the quality, coverage and representativeness of the indices. **Hence, statement 1 is not correct.**
- Wholesale price index calculated with 2011-12 base year does not include indirect taxes in order to remove the impact of fiscal policy. This also brings the present WPI series closer to Producer Price Index, as is practised globally. **Hence, statement 2 is not correct.**
- RBI has been mandated to achieve price stability measured in terms of CPI inflation. **Hence, statement 3 is not correct.**
- सरकार द्वारा पूरे भारत के लिए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार वर्ष 2004-05 को परिवर्तित कर 2011-12 निर्धारित किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनागत परिवर्तन करने के लिए तथा संकेतकों की गुणवत्ता, कार्यक्षेत्र एवं प्रभाव में सुधार करने के लिए सूक्ष्म आर्थिक संकेतकों के आधार वर्ष में परिवर्तन करना एक नियमित प्रक्रिया है। **अत; कथन 1 सही नहीं है।**
- नए आधार वर्ष, 2011-12, के अनुसार किये गये थोक मूल्य सूचकांक की गणना में, राजकोषीय नीति के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया गया है। यह वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला को वैश्विक स्तर पर प्रचलित उत्पादक मूल्य सूचकांक से समानता प्रदान करता है। **इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।**
- RBI द्वारा CPI मुद्रास्फीति के संदर्भ में मूल्य स्थिरता प्राप्त करने का अधिदेश दिया गया है। **इसलिए, कथन 3 सही नहीं है।**

17.D

- **Peer-to-peer lending is a form of crowd-funding used to raise loans for people who need to borrow, from people who want to invest.**
- **It enables individuals to borrow and lend money without any financial institution as an intermediary, and extends credit to borrowers who are unable to get it through traditional financial institutions.**
- The main idea is savers getting higher interest by lending out their money instead of saving it, and borrowers getting funds at comparatively low interest rates.
- It typically uses an online platform where the borrowers and lenders register themselves. Due diligence is carried out before allowing the parties to participate in any lending or borrowing activity.
- **All P2P platforms will now be considered non-banking financial companies and regulated by the RBI.**
- **पीयर टू पीयर लेंडिंग, क्राउड-फंडिंग का एक रूप है जिसका उपयोग ऋण की आवश्यकता वाले लोंगों के लिए निवेश हेतु इच्छुक लोगों से ऋण जुटाने के लिए किया जाता है।**
- **यह बिना किसी वित्तीय संस्थान की मध्यस्थता के, किसी व्यक्ति को धन उधार लेने और देने में सक्षम बनाता है और उन उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करता है जो इसे पारम्परिक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से प्राप्त करने में असमर्थ हैं।**
- इसके पीछे मूल धारणा यह है कि बचतकर्ता अपनी बचत की अपेक्षा अपने धन को उधार देकर ब्याज के रूप में अधिक लाभ प्राप्त करता है तथा उधारकर्ताओं को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर धन (उधारी) प्राप्त हो जाता है।
- इसमें सामान्यतः एक ऑनलाइन मंच का उपयोग किया जाता है जहां उधारकर्ता और उधारदाता स्वयं को पंजीकृत करते हैं। पक्षकारों को किसी भी ऋण या उधार गतिविधि में भाग लेने की स्वीकृति देने से पूर्व पर्याप्त जांच की जाती है।
- **सभी P2P प्लेटफॉर्म को अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में माना जाएगा और RBI द्वारा विनियमित** किया जाएगा।

18.B

Marginal standing facility (MSF) is a window for banks to borrow from the Reserve Bank of India in an emergency situation when inter-bank liquidity dries up completely. Banks borrow from the central bank by pledging government securities at a rate higher than the repo rate under liquidity adjustment facility or LAF in short. Currently the MSF rate is pegged 25 basis points above the repo rate. Under MSF, banks can borrow funds up to one percentage of their net demand and time liabilities (NDTL).

सीमांत स्थायी सुविधा ('मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी' :MSF): जब इंटर-बैंकिंग लिक्विडिटी (अंतर-बैंक तरलता) पूर्णत: समाप्त हो जाती है तो ऐसी आपातकालीन स्थिति में बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने की सुविधा को MSF कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंक तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility: LAF) के तहत उपलब्ध रेपो रेट से भी अधिक उच्च दर पर सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं। वर्तमान में MSF की दर रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट्स (आधार बिंदु) अधिक निर्धारित की गई है। **MSF** के अंतर्गत, बैंक अपनी निवल मांग एवं मीयादी देयताओं (Net Demand and Time Liabilities: NDTL) के एक प्रतिशत तक राशि उधार ले सकते हैं।

19.A

- **Statement 1 is correct:** Debt-for-nature swaps (DFNs) draw on the linkage between reducing a country's debt and protecting its environment. DFNs are typically a voluntary transaction in which an amount of hard-currency debt owed by a developing country government (debtor) is cancelled or reduced (i.e., discounted) by a creditor, in exchange for financial commitments to conservation -- in local currency -- by the debtor. Creditors in these transactions can be developed country governments, commercial banks and even commercial supplier companies (e.g., companies that provide construction materials on credit for government projects).
- **Statement 2 is not correct:** The proceeds generated from DFNs are often administered by local conservation or environmental trust funds, that disburse grants to specific projects and ensure accountable, transparent and decentralized management.
- **कथन 1 सही है:** डेब्ट फॉर नेचर स्वैप (DFNs) किसी देश का ऋण कम करने और उसके पर्यावरण की सुरक्षा करने के मध्य संबंध को रेखांकित करता है। DFNs एक प्रकार के स्वैच्छिक लेन-देन होते हैं। इसमें विकासशील देशों (ऋणी) के ऊपर बकाये ऋण (अर्थात् हार्ड करेंसी ऋण) की राशि को संरक्षण कार्यों के लिए उनके वित्तीय प्रतिबद्धताओं के स्थान पर ऋणदाता द्वारा निरस्त या कम (स्थानीय मुद्रा में) कर दिया जाता है (अर्थात, छूट प्रदान की जाती है)। इन लेनदेनों में ऋणदाता विकसित देशों की सरकारें, वाणिज्यिक बैंक और यहां तक कि वाणिज्यिक आपूर्तिकर्ता कंपनियां (उदाहरण के लिए, सरकारी परियोजनाओं के लिए क्रेडिट पर निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने वाली कंपनियां) हो सकती हैं।
- **कथन 2 सही नहीं है:** DFNs से उत्पन्न होने वाली आय का प्रशासन प्राय: स्थानीय संरक्षण या एनवायरनमेंट ट्रस्ट फंड द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदान संवितरित करते हैं और जवाबदेह, पारदर्शी और विकेन्द्रीकृत प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं।

20.D

Inflation is the rate at which the general level of prices for goods and services is rising and, consequently, the purchasing power of currency is falling. Central banks attempt to limit inflation, and avoid deflation, in order to keep the economy running smoothly.

Inflation can arise from internal and external events

Some inflationary pressures direct from the domestic economy, for example the decisions of utility businesses providing electricity or gas or water on their tariffs for the year ahead, or the pricing strategies of the food retailers based on the strength of demand and competitive pressure in their markets. **Hoarding, cartelization, speculations could lead to inflationary trend in the economy**.

Hoarding is the purchase of large quantities of a commodity by a speculator with the intent of pushing up the price. A speculator hoping to increase the price of a commodity can do so by leveraging demand for it by buying physical inventory as well as purchasing futures contracts for that commodity. Hoarding can also take place in financial instruments like bonds.

Speculation is the act of trading in an asset or conducting a financial transaction that has a significant risk of losing most or all of the initial outlay with the expectation of a substantial gain. With speculation, the risk of loss is more than offset by the possibility of a huge gain, otherwise there would be very little motivation to speculate. Hence, more speculation will lead to greater inflationary trend.

Cartel is a collection of otherwise independent businesses or countries that act together as if they were a single producer and thus are able to fix prices for the goods they produce and the services they render without competition. Hence the monopolistic prices of goods leads to inflation.

- मुद्रास्फ़ीति वह दर है जिस पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि होती है और इसके फलस्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को सीमित करने और अपस्फीति से बचाने का प्रयास करता है।
- **मुद्रास्फीति आंतरिक और बाहरी घटनाओं से उत्पन्न हो सकती है।**
- कुछ मुद्रास्फीतिकारी दबाव घरेलू अर्थव्यवस्था से निर्देशित होते हैं, उदाहरण के लिए विद्युत या गैस या जल उपलब्ध कराने वाले यूटिलिटी बिजनेस का आगामी वर्ष के लिए अपने प्रशुल्कों पर निर्णय या मांग की क्षमता पर आधारित खुदरा खाद्य पदार्थ, विक्रेताओं की मूल्य निर्धारण की रणनीतियां और बाजारों में प्रतिस्पर्धी दबाव। **जमाखोरी, कार्टेलाइजेशन, सट्टेबाजी से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है।**
- **जमाखोरी वस्तुतः** सट्टेबाज द्वारा कीमतें बढ़ाने के उद्देश्य से वस्तुओं की बड़ी मात्रा में की जाने वाली खरीद होती है। वस्तुओं की कीमत में वृद्धि की आशा करने वाला सट्टेबाज भौतिक स्टॉक खरीदने के साथ-साथ वायदा अनुबंध का क्रय कर, वस्तु के लिए मांग का लाभ उठाने के लिए ऐसा कर सकता है। बांड्स जैसे वित्तीय विपत्रों में भी जमाखोरी हो सकती है।

- **सट्टेबाजी** परिसंपत्ति में व्यापार या वित्तीय लेनदेन करने का कार्य है जिसमें अत्यधिक लाभ की आशा के साथ अधिकांश या सभी प्रारंभिक परिव्यय गंवाने का जोखिम होता है। सट्टेबाजी के साथ, नुकसान का जोखिम बड़े लाभ की संभावना द्वारा प्रतिसंतुलित किए जाने से अधिक होता है, अन्यथा सट्टेबाज के लिए बहुत कम अभिप्रेरणा होगी। इसलिए, अधिक सट्टेबाजी अधिक मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को जन्म देती है।
- **व्यवसायी समूहन (कार्टेल)** स्वतंत्र व्यापारों या ऐसे देशों का समूह होता है जो इस तरह एक साथ कार्य करते हैं, जैसे कि वे एक एकल उत्पादक हों। इस प्रकार वे बिना प्रतिस्पर्धा के उन वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारित करते हैं जिनका वे उत्पादन करते हैं। इसलिए वस्तुओं की कीमतों पर इस प्रकार की एकाधिकार प्रवृत्ति मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है।

21.D

The currency deposit ratio shows the amount of currency that people hold as a proportion of aggregate deposits. **Hence, statement 1 is correct.**

An increase in cash deposit ratio leads to a decrease in money multiplier.An increase in deposit rates will induce depositors to deposit more, thereby leading to a decrease in Cash to Aggregate Deposit ratio. This will in turn lead to a rise in Money Multiplier.

CDR reflects people's preference for liqidity. It is purely behavioural parameter which depends, among other things, on the seasonal pattern of expenditure. CDR increases during the festive season as people convert deposits to cash balance for meeting extra expenditure during such periods. **Hence, statement 2 and 3 are correct.**

- करेंसी जमा अनुपात (करेंसी डिपाजिट रेशो: CDR) मुद्रा की उस मात्रा को दर्शाती है, जो लोगों के पास उनकी कुल जमाराशि के अनुपात के रूप में रखी जाती है। **इसलिए, कथन 1 सही है।**
- नकदी जमा अनुपात में होने वाली वृद्धि के कारण मनी मल्टीप्लायर में कमी आती है। जमा दर में वृद्धि होने से जमाकर्ताओं को और अधिक मुद्रा जमा करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे (जमाराशि अनुपात की तुलना में) CDR में कमी आती है। CDR वस्तुतः तरलता के प्रति जनता के वरीयता को प्रदर्शित करता है। यह पूर्णतः एक व्यवहार संबंधी मानदंड है जो अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त व्यय के मौसमी प्रवृत्ति को दर्शाती है। त्योहारों के मौसम में CDR में वृद्धि होती है, क्योंकि ऐसे अवसरों पर लोग सामान्यतया अपने अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अपनी बैंक जमाओं में कमी कर अपने पास उपलब्ध नकदी में वृद्धि करते हैं। **इसलिए, कथन 2 और 3 सही हैं।**

22.B

- **A bear market is one that is in decline**. Share prices are continuously dropping, resulting in a downward trend that investors believe will continue in the long run, which, in turn, perpetuates the spiral. During a bear market, **the economy will typically slow down and unemployment will rise** as companies begin laying off workers. **In a bear market, investors rush to sell their stocks before they lose more value.**
- A bull market refers to a market that is on the rise. It is typified by a sustained increase in market share prices. In such times, investors have faith that the uptrend will continue in the long term. Typically, the country's economy is strong and employment levels are high. Typically, the country's economy is strong and employment levels are high.
- **मंदड़िया बाजार वह दशा है जब बाज़ार में गिरावट की स्थिति व्याप्त हो।** इस स्थिति के दौरान शेयर की कीमतें लगातार गिरती जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक अधोगामी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इस स्थिति में निवेशकों का यह मानना कि यह प्रवृत्ति लंबे समय तक जारी रहेगी, भविष्य में उत्तरोत्तर कमी को जारी रखता है। मंदड़िया बाजार के दौरान **अर्थव्यवस्था आमतौर पर मंद हो जाती है और बेरोजगारी में वृद्धि होती है** क्योंकि कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी प्रारंभ कर देती हैं। **मंदड़िया बाजार में निवेशक अधिक मूल्य खोने से पहले अपने स्टॉक को बेचने का प्रयास करते हैं।**
- बाजार की ऐसी दशा को जिसमें वृद्धि की स्थिति व्याप्त हो, 'तेजड़िया बाजार' से संदर्भित किया जाता है। यह बाजार में शेयर की कीमतों में निरंतर वृद्धि से संबंधित होता है। ऐसे समय में निवेशकों को यह भरोसा होता है कि वृद्धि लंबी अवधि तक जारी रहेगी। आमतौर पर इससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है और रोजगार का स्तर उच्च होता है।

23.B

Bangalore-Chennai industrial region mainly comprise of cities like Bangalore, Mysore, Salem, Madurai, Chennai, Coimbatore etc.Gondwana coal is good quality coal in terms of calorific value, it is not present in this region. However in Tamil Nadu's Neyveli Coalmine we can find lignite coal which is inferior to Gondawana coal and cannot be used in thermal power plants. The power supply in this region was fulfilled by Pykara hydroelectric plant. **Hence, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct.**

Tamil Nadu is one of the cotton growing state of India because of favourable soil and climate and cotton textile industries has developed in this region. **Hence statement 3 is correct.**

Major oil fields are in Gujarat and Assam. We have natural gas reserve in the eastern shorelines of Tamil Nadu and recently oil refinery has come up but we do not have oil field there. **Hence statement 4 is incorrect.**

- बंगलुरु-चेन्नई औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य रूप से बंगलुरु, मैसूर, सलेम, मदुरै, चेन्नई, कोयम्बटूर आदि शहर सम्मिलित हैं। कैलोरी मान की दृष्टि से गोंडवाना कोयला अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला होता हैं, यह इस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। हालांकि तमिलनाडु के निवेली कोयला खदानों में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यह गोंडवाना कोयला से निम्न स्तर का होता है और ताप विद्युत संयंत्रों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति को पायकारा जलविद्युत संयंत्र द्वारा पूरी की जाती थी। **इसलिए, कथन 1 सही नहीं है और कथन 2 सही है।**

- तमिलनाडु अनुकूल मृदा और जलवायु के कारण भारत के कपास उत्पादक राज्यों में से एक है और इस क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। **इसलिए कथन 3 सही है।**
- प्रमुख तेल क्षेत्र गुजरात और असम में उपस्थित हैं। तमिलनाडु के पूर्वी तटीय इलाकों में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं और हाल में, तेल शोधनशालाएं भी स्थापित की गईं हैं लेकिन वहां तेल क्षेत्र उपस्थित नहीं है। **अतः कथन 4 सही नहीं है।**

24.A

Components of Balance of Payments: (1) Current Account; (2) Capital Account

(1) Current Account:

Current account refers to an account which records all the transactions relating to export and import of goods and services and unilateral transfers during a given period of time. Current account contains the receipts and payments relating to all the transactions of visible items, invisible items and unilateral transfers.

(2) Capital Account:

Capital account of BOP records all those transactions, between the residents of a country and the rest of the world, which cause a change in the assets or liabilities of the residents of the country or its government. It is related to claims and liabilities of financial nature.

Capital Account is used to:

(i) Finance deficit in current account; or

(ii) Absorb surplus of current account.

Capital account is concerned with financial transfers. So, it does not have direct effect on income, output and employment of the country.

Components of Capital Account:

1. Borrowing and lending to and from abroad: It includes:

A. All transactions relating to borrowings from abroad by private sector, government, etc. Receipts of such loans and repayment of loans by foreigners are recorded on the positive (credit) side.i.e. **External commercial borrowing (ECB)**

B. All transactions of lending to abroad by private sector and government. Lending abroad and repayment of loans to abroad is recorded as negative or debit item.

2. Investments to and from abroad: It includes:

A. Investments by rest of the world in shares of Indian companies, real estate in India, etc. Such investments from abroad are recorded on the positive (credit) side as they bring in foreign exchange.i.e.- **Foreign direct investment, foreign portfolio investment, etc forms part of capital account.**

B. Investments by Indian residents in shares of foreign companies, real estate abroad, etc. Such investments to abroad be recorded on the negative (debit) side as they lead to outflow of foreign exchange.

3. Change in Foreign Exchange Reserves:

The foreign exchange reserves are the financial assets of the government held in the central bank. A change in reserves serves as the financing item in India's BOP. So, any withdrawal from the reserves is recorded on the positive (credit) side and any addition to these reserves is recorded on the negative (debit) side. It must be noted that 'change in reserves' is recorded in the BOP account and not 'reserves'.

Hence, all given options are correct.

भुगतान संतुलन के घटक हैं: (1) चालू खाता; (2) पूँजी खाता

(1) चालू खाता:

चालू खाता एक ऐसे खाते को संदर्भित करता है जो किसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात एवं आयात तथा एकपक्षीय अंतरणों से संबंधित सभी लेन-देनों को अभिलिखित करता है। चालू खाते में दृश्य मदें, अदृश्य मदें और एकपक्षीय अंतरणों के सभी लेनदेनों से संबंधित प्राप्तियां तथा भुगतान सम्मिलित होती हैं।

(2 पूँजी खाता:

भुगतान संतुलन (BOP) का पूंजी खाता, देश के निवासियों और दुनिया के शेष भागो के मध्य, उन सभी लेन-देनों को अभिलिखित करता है, जो देश के निवासियों या इसकी सरकार के परिसंपत्तियों या देयता में परिवर्तन के कारण होता है। यह वित्तीय प्रवृति के दावों और देयता से संबंधित है।

पूँजी खाते का उपयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है:

(i) चालू खाते के घाटा के वित्तीयन में; या

(ii) चालू खाते के अधिशेष को ग्रहण करने में।

पूंजी खाता वित्तीय अंतरणों से संबंधित है। इसलिए, इसका देश की आय, उत्पादन तथा रोजगार पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है।

पूंजी खाते के घटक:

1. **विदेशों से ऋण लेना तथा विदेशों में ऋण देना: इसमें सम्मिलित हैं:**

A. निजी क्षेत्र, सरकार आदि द्वारा विदेश से लिए गये ऋणों से संबंधित सभी अंतरण। साथ ही ऋणों की प्राप्तियों तथा विदेशियों द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान को इस खाते की क्रेडिट मद की तरफ अभिलिखित किया जाता है।
B. निजी क्षेत्र और सरकार द्वारा विदेश में दिए गये ऋणों से संबंधित सभी अंतरण। विदेश में दिए गये ऋण और विदेशों में ऋणों के पुनर्भुगतान को डेबिट मद के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

1. **विदेशों में निवेश तथा विदेशों से निवेश: इसमें सम्मिलित हैं:**

A. भारतीय कंपनियों के शेयरों, भारत की अचल संपत्ति आदि में शेष विश्व द्वारा किये गये निवेश। विदेश से ऐसे निवेश क्रेडिट (सकारात्मक) मद में अभिलिखित किये जाते हैं, क्योंकि ये विदेशी मुद्रा को लाते हैं। अर्थात् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, आदि पूंजी खाते में शामिल होते हैं।
B. भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी कंपनियों के शेयरों, विदेशी अचल संपत्ति में निवेश। विदेश में किए गए ऐसे निवेश डेबिट (नकारात्मक) मद में अभिलिखित किए जाते हैं क्योंकि ये विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रवाह करते हैं।

3. विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन:

विदेशी मुद्रा भंडार वस्तुतः केंद्रीय बैंक में पास सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियां होती हैं। इस आरक्षित निधि में कोई भी परिवर्तन भारत के भुगतान संतुलन (BOP) को प्रभावित करता है। इसलिए, आरक्षित निधि से किया गया कोई भी प्रत्याहार, धनात्मक (क्रेडिट) मद में अभिलिखित किया जाता है और इन आरक्षित निधि में की गई किसी भी अनुवृद्धि को ऋणात्मक (डेबिट)) मद में अभिलिखित किया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरक्षित निधि में परिवर्तन' को भुगतान संतुलन (BOP) खाते में दर्ज किया जाता है, 'आरक्षित निधि' नहीं।

इसलिए, सभी दिए गए विकल्प सही हैं।

25.C

ETFs are essentially index funds that are listed and traded on stocks exchanges just like regular shares.
ETFs were started in 2001 in India. They comprise a portfolio of equity, bonds and trade close to its net asset value. These funds mainly track an index, a commodity, or a pool of assets.
ETFs experience price changes throughout the day as they are bought and sold. ETFs typically have higher daily liquidity and lower fees than mutual fund shares, making them an attractive alternative for individual investors.

Hence, both the statements are correct.

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs) अनिवार्यतः इंडेक्स फंड होते हैं। इनका नियमित शेयरों के समान इन्हें स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाता है और इनका कारोबार किया जाता है।
भारत में ETF की शुरुआत 2001 में की गयी थी। इसमें इक्विटी, बॉन्ड और व्यापार शामिल होता है जो उसके शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के लगभग समान होता है। ये फंड मुख्य रूप से एक सूचकांक, एक वस्तु या परिसंपत्तियों के पूल पर नज़र रखते हैं।
ETF का दिनभर क्रय-विक्रय के दौरान मूल्य परिवर्तित होता रहता है। ETFs में सामान्य रूप से म्यूचुअल फंड शेयरों की तुलना में उच्चतर दैनिक तरलता एवं निम्न शुल्क होता है, जिसके परिणामस्वरूप ये व्यक्तिगत निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाते हैं।

इसलिए, दोनों कथन सही हैं।

26.D

General Anti Avoidance Rules is a set of laws aimed at **curtailing tax avoidance in general**.
In India, the GAAR concept was introduced with the DTC (Direct Tax Code) Bill on August 2009. Later, a revised discussion paper was released with provisions containing the GAAR under DTC Bill 2010. The bill aimed to introduce the GAAR involving DTC from 1st April 2012 onwards. But several of its provisions were criticized because of lack of clarity, lack of safeguards and increased scope for subjective authorization by the tax officials.
The government subsequently set up a panel under Parthasarathy Shome to review the proposals. The Committee, suggested that the rules be deferred by three years, arguing that more time is needed to create administrative machinery for its implementation and called for intensive training of officials.

- जनरल एंटी अवायडेंस रूल्स (GAAR), कानूनों का ऐसा समुच्चय है जिसका लक्ष्य सामान्य रूप से **कर अपवंचना (tax avoidance)** की प्रवृत्ति में कमी लाना है।
- भारत में GAAR संबंधी संकल्पना को DTC (प्रत्यक्ष कर संहिता) विधेयक के साथ अगस्त, 2009 में पुरःस्थापित किया गया। इसके पश्चात, DTC विधेयक, 2010 के अंतर्गत GAAR संबंधी प्रावधानों के साथ एक संशोधित पत्र ज़ारी किया गया। इस विधेयक का लक्ष्य 1 अप्रैल, 2012 से DTC को सम्मिलित करते हुए GAAR को पुरःस्थापित करना था। GAAR से संबंधित प्रावधानों को 2012-13 के बजट के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री के द्वारा पुरःस्थापित किया गया था। किन्तु इसके प्रावधानों में अस्पष्टता, सुरक्षा का अभाव तथा कर अधिकारियों द्वारा व्यक्तिपरक अनुमोदन के बढ़ते हुए कार्य क्षेत्र के कारण इसके कई प्रावधानों को लेकर आलोचना भी की गयी ।
- इसके पश्चात सरकार द्वारा पार्थसारथी सोम के नेतृत्व में प्रस्तावों के पुनर्मूल्यांकन हेतु एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि नियमों को तीन वर्षों तक के लिए विलम्बित किया जाए। यह तर्क देते हुए कि इसके कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक ढांचे के निर्माण हेतु अधिक समय की आवश्यकता हैं तथा अधिकारियों के गहन प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जानी है।

27.A

In economics, a J Curve refers to a change in the country's balance of trade, following a currency devaluation or depreciation.Immediately after the devaluation of a currency, the immediate reaction is that exports will remain unchanged while imports will increase. A weak currency means that the imports will be costly, while it will be less valuable to export commodities. The imbalance leads to a fall in the current accounts, hence a smaller surplus or a bigger deficit. The high cost of imports will reduce the import volume, and this will cause the volume of exports to rise due to the more competitive prices of foreign buyers. Foreign buyers will be attracted to lower-priced local products. Since domestic consumers will buy less of the imported goods, they will purchase comparable local products that are more affordable than the foreign-originated goods.

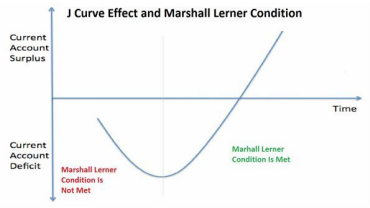

- **अर्थशास्त्र में, J वक्र मुद्रा के अवमूल्यन के पश्चात देश के व्यापार संतुलन में परिवर्तन को संदर्भित करता है। मुद्रा के अवमूल्यन के तुरंत पश्चात, होने वाली तात्कालिक प्रतिक्रिया के तहत निर्यात अपरिवर्तित बने रहते हैं, जबकि आयात में वृद्धि होती है।** कमजोर मुद्रा (weak currency) का तात्पर्य एक ऐसी मुद्रा से है जिससे किया गया आयात महंगा होगा, जबकि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए यह कम मूल्यवान होगी। असंतुलन के कारण चालू खाते में गिरावट आती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिशेष में कमी या घाटे में वृद्धि हो जाती है। आयात की उच्च लागत से आयात की मात्रा में कमी हो जाती है और इससे विदेशी खरीदारों की अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों के कारण इससे निर्यात की मात्रा में वृद्धि होती है। विदेशी खरीदार कम कीमतों वाले स्थानीय उत्पादों की ओर आकर्षित होते हैं। चूँकि घरेलू उपभोक्ता आयातित वस्तुएं कम क्रय करते हैं, वे तुलनात्मक स्थानीय उत्पाद क्रय करते हैं जो आयातित वस्तुओं की तुलना में अधिक वहनीय होती हैं।

28.C

Generalized System of Preferences (GSP) is a preferential tariff system extended by developed countries (also known as preference-giving countries or donor countries) to developing countries (also known as preference receiving countries or beneficiary countries). It involves reduced MFN Tariffs or duty-free entry of eligible products exported by beneficiary countries to the markets of donor countries.

Benefits Of GSP

1. Indian exporters benefit indirectly - through the benefit that accrues to the importer by way of reduced tariff or duty-free entry of eligible Indian products.
2. Reduction or removal of import duty on an Indian product makes it more competitive to the importer - other things (e.g. quality) being equal.
3. This tariff preference helps new exporters to penetrate a market and established exporters to increase their market share and to improve upon the profit margins, in the donor country.

'जनरलाइज़्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस' (GSP) विकसित देशों (जिन्हे प्रेफरेंस देने वाले देशों या दाता देशों के रूप में भी जाना जाता है) द्वारा विकासशील देशों (जिन्हें प्रेफरेंस प्राप्त करने वाले देशों या लाभार्थी देशों के रूप में भी जाना जाता है) के लिए विस्तारित एक अधिमान्य प्रशुल्क व्यवस्था (प्रेफेरेंशिअल टैरिफ सिस्टम) है। इसमें दाता देशों के बाजारों में लाभार्थी देशों द्वारा निर्यात किए गए कुछ निर्दिष्ट (एलिजिबल) उत्पादों पर मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) प्रशुल्क की निम्न दरों पर या प्रशुल्क मुक्त प्रवेश शामिल है।

GSP के लाभ:

- भारतीय निर्यातकों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ - ये लाभ कुछ निर्दिष्ट भारतीय उत्पादों के लिए अल्प प्रशुल्क दरों या प्रशुल्क मुक्त प्रवेश के परोक्ष रूप में भारतीय निर्यातकों को प्राप्त होते हैं ।
- अन्य पहलुओं (जैसे- गुणवत्ता) के समान होने पर, किसी भारतीय उत्पाद पर आयात शुल्क में कमी या उसके समाप्त होने से वह उत्पाद आयातक के लिए और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन जाता है।
- यह अधिमानी प्रशुल्क व्यवस्था दाता देश में, नए निर्यातकों को बाजार में पैठ बनाने के लिए तथा प्रतिष्ठित निर्यातकों को अपनी बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि करने एवं लाभ प्रतिशतता में सुधार करने में सहायता प्रदान करता है।

29.C

A red herring is a preliminary prospectus filed by a company with Securities and Exchange Board of India (SEBI) usually in connection with the company's initial public offering. A red herring prospectus contains most of the information pertaining to the company's operations and prospects but does not include key details of the issue, such as its price and the number of shares offered. **Hence, the correct option is (c).**

विकल्प C सही है। रेड हेरिंग एक प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस है, जिसे एक कंपनी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास कम्पनी के इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के समय में दाखिल किया जाता है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में अधिकांश सूचनाएं कंपनी के संचालन और संभावनाओं से संबंधित होती हैं, लेकिन इसमें निर्गम से सम्बंधित महत्वपूर्ण विवरण, जैसे कि जारी किए गए शेयरों की संख्या और कीमत सम्मिलित नहीं होते हैं।

30.D

The World Bank Group consists of five organizations:

- **The International Bank for Reconstruction and Development**: The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) lends to governments of middle-income and creditworthy low-income countries.
- **The International Development Association:** The International Development Association (IDA) provides interest-free loans and grants to governments of the poorest countries. Together, IBRD and IDA make up the World Bank.
- **The International Finance Corporation:** The International Finance Corporation (IFC) is the largest global development institution focused exclusively on the private sector. It helps developing countries achieve sustainable growth by financing investment, mobilizing capital in international financial markets, and providing advisory services to businesses and governments.
- **The Multilateral Investment Guarantee Agency:** The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) was created in 1988 to promote foreign direct investment into developing countries to support economic growth, reduce poverty, and improve people's lives. MIGA fulfills this mandate by offering political risk insurance (guarantees) to investors and lenders.
- **The International Centre for Settlement of Investment Disputes:** The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) provides international facilities for conciliation and arbitration of investment disputes. **Hence, option (d) is correct.**

विश्व बैंक समूह में पांच संगठन सम्मिलित हैं:

- **अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट : IBRD):** IBRD द्वारा मध्यम आय और क्रेडिट योग्य निम्न आय वाले देशों की सरकारों को ऋण प्रदान किया जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन : IDA):** IDA द्वारा सबसे निर्धन देशों की सरकारों को ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान प्रदान किया जाता है। IBRD और IDA सम्मिलित रूप से विश्व बैंक का निर्माण करते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन : IFC):** IFC विश्व का सबसे बड़ा विकास संगठन है जो अनन्य रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित है। यह निवेश का वित्तपोषण कर, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों से पूंजी को एकत्र करने में सहायता कर और व्यापार एवं सरकारों को सलाहकारी सेवाएं प्रदान कर विकासशील देशों को संधारणीय विकास की प्राप्ति में सहायता करता है।
- **बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी : MIGA):**1988 में MIGA को विकासशील देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, गरीबी को कम करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने हेतु निर्मित किया गया था। MIGA निवेशकों और ऋणदाताओं को राजनीतिक जोखिम बीमा (गारंटी) के प्रस्ताव द्वारा अपने इस दायित्व को पूरा करती है।
- **निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ़ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स : ICSID):** ICSID निवेश विवादों के समझौते और मध्यस्थता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करता है। **इसलिए, विकल्प D सही है।**

31.C

banks in India have shifted to a new methodology to compute their lending rate- Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR). MCLR refers to the minimum interest rate of a bank below which it cannot lend, except in some cases allowed by the RBI. **RBI decided to shift from base rate to MCLR because the rates based on marginal cost of funds are more sensitive to changes in the policy rates**.

This is very essential for the effective implementation of monetary policy. Prior to MCLR system, different banks were following different methodology for calculation of base rate /minimum rate – that is either on the basis of average cost of funds or marginal cost of funds or blended cost of funds. Thus, MCLR aims

- **To improve the transmission of policy rates into the lending rates of banks.**
- To bring transparency in the methodology followed by banks for determining interest rates on advances.
- **To ensure availability of bank credit at interest rates which are fair to borrowers as well as banks.**
- To enable banks to become more competitive and enhance their long run value and contribution to economic growth. **Banks review and publish their MCLR of different maturities, every month, on a pre-announced date.**

भारत में बैंकों ने अपनी उधार दर (लेंडिंग रेट) की गणना करने के लिए MCLR नामक एक नई पद्धति को अपनाया है। कोषों (फंड्स) की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ़ फ़ंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट: MCLR) उस न्यूनतम ब्याज दर को संदर्भित करती है जिस दर से नीचे की दर पर, RBI द्वारा स्वीकृत कुछ मामलों को छोड़कर, बैंक ऋण नहीं दे सकता है। RBI ने बेस रेट को MCLR से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है क्योंकि **कोषों (फंड्स) की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर (पॉलिसी रेट्स) में परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।**

मौद्रिक नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। MCLR प्रणाली से पूर्व, विभिन्न बैंक आधार दर / न्यूनतम दर की गणना के लिए अलग-अलग पद्धतियों का अनुसरण कर रहे थे - जो या तो निधि की औसत लागत या निधि की सीमांत लागत अथवा निधि की मिश्रित लागत के आधार पर होती थीं। इस प्रकार MCLR का उद्देश्य है:

- **बैंकों की ऋण दरों में नीतिगत दरों के संचरण (ट्रांसमिशन) में सुधार करना।**
- अग्रिम पर ब्याज दरों के निर्धारण हेतु बैंकों द्वारा अनुसरण की जाने वाली पद्धति में पारदर्शिता लाना।
- उन **ब्याज दरों पर बैंक-ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना जो उधारकर्ताओं के साथ-साथ बैंकों के लिए भी उचित हों।**
- बैंकों को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनने और उन्हें उनके दीर्घकालिक मूल्य एवं आर्थिक विकास में योगदान को बढ़ाने के लिए सक्षम बनाना। **बैंक प्रत्येक माह पूर्व-घोषित तिथि पर अपनी विभिन्न परिपक्वताओं (maturities) की MCLR की समीक्षा और प्रकाशन करते हैं।**

32.C

An Angel Investor is an affluent individual who provides capital for a business start-up, usually in exchange for ownership equity. Often, angel investors are among an entrepreneur's family and friends. Angel investors provide more favorable terms compared to other lenders, since they usually invest in the entrepreneur starting the business rather than the viability of the business. Angel investors are focused on helping startups take their first steps, rather than the possible profit they may get from the business. **Hence, Statement 1 is correct.**
Statement 2 is correct: As per SEBI's classification, Angel fund is a sub-category of Venture Capital Fund under Category I of Alternative Investment Funds.

- एंजेल इन्वेस्टर एक धनी व्यक्ति होता है, जो सामान्यतः ऑनरशिप इक्विटी के बदले में किसी बिज़नेस स्टार्ट-अप के लिए पूंजी उपलब्ध कराता है। प्रायः एंजेल इन्वेस्टर्स किसी उद्यमी के परिवार और सहयोगियों से ही संबंधित होते हैं। एंजेल इन्वेस्टर्स अन्य ऋणदाताओं की तुलना में अधिक अनुकूल शर्तें रखते हैं, क्योंकि वे सामान्यतः व्यवसाय की व्यवहार्यता के स्थान पर व्यवसाय आरंभ करने वाले उद्यमी पर निवेश करते हैं। एंजेल इन्वेस्टर्स व्यवसाय से संभावित लाभ की प्राप्ति के बजाय स्टार्ट-अप को आरंभ करने हेतु सहायता पर फोकस करते हैं।**अतः, कथन 1 सही है।**
- कथन 2 **सही है:** सेबी (SEBI) के वर्गीकरण के अनुसार, एंजेल इन्वेस्टर फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की श्रेणी I के अंतर्गत वेंचर कैपिटल फंड की एक उप-श्रेणी है।

33.C

Factors of production are the inputs required in production of a good. Land, labour, physical capital and human capital are considered as major factors of production. Physical capital are of two types fixed capital and working capital.Fixed capital are those which can be used in production over many years. Tools, machines, and buildings come under fixed capital. Tools and machines range from very simple tools such as a farmer's plough to sophisticated machines such as generators, turbines, computers etc. **Hence, option 2 is incorrect.**
Working capitals are those which are used up in production and cannot be used again. Raw materials and money in hand come under working capital. Various raw materials can be yarn used by weaver and the clay used by potter. Also, some money is always required to make payments and buy other items. **Hence, options 1 and 3 are correct.**

- वस्तुओं के उत्पादन हेतु आवश्यक आगतों को उत्पादन कारक कहा जाता है। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी प्रमुख उत्पादन कारक हैं। भौतिक पूंजी के दो प्रकार हैं- स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थिर पूंजी वह होती है, जिसका उपयोग उत्पादन में कई वर्षों तक किया जा सकता है। इसके अंतर्गत शामिल हैं- उपकरण, मशीन एवं भवन। उपकरण और मशीनें अत्यंत सरल प्रकृति के उपकरणों जैसे कि किसान के हल से लेकर परिष्कृत प्रकृति के उपकरणों जैसे जेनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर इत्यादि प्रकार के हो सकते हैं। **इसलिए, विकल्प 2 सही नहीं है।**
- कार्यशील पूंजी वह होती है जिसका उत्पादन में एक बार उपयोग होने के पश्चात पुनः उपयोग संभव नहीं है तथा इसके अंतर्गत शामिल हैं- कच्चा माल एवं नकद राशि। कच्चे माल के उदाहरणों में शामिल हैं- बुनकरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला सूती धागा और कुम्हार द्वारा उपयोग की जाने वाली मिट्टी। इसके अतिरिक्त भुगतान करने तथा वस्तुओं की खरीद के लिए कुछ नकद की आवश्यकता सदैव होती है। **इसलिए, विकल्प 1 और 3 सही है।**

34.A

- **Tax Inspectors Without Borders (TIWB) is a joint initiative of Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and United Nations Development Programme (UNDP).** The TIWB Initiative facilitates targeted, tax audit assistance programmes in developing countries across the globe. **The TIWB Initiative is a strong response to the attention given to effective and efficient mobilisation of domestic resources in achieving the Sustainable Development Goals and the commitments made by the international community in Addis Ababa to strengthen international tax cooperation.**
- The TIWB initiative facilitates the transfer of tax audit knowledge and skills to developing country tax administrations using a practical, "learning by doing" approach. Experienced tax auditors work on current tax audits and international tax issues alongside local tax officials in assistance-requesting countries under a TIWB programme whereby they share their expertise and skills.
- A joint OECD/UNDP TIWB Secretariat based in Paris and supported by UNDP's network of Country Offices in developing countries that establishes, coordinates and facilitates each TIWB expert deployment.
- **टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (TIWB) वस्तुतः आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme: UNDP)** की एक संयुक्त पहल है। TIWB पहल वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों में लक्षित, टैक्स ऑडिट असिस्टेंस प्रोग्राम (कर लेखा परीक्षा सहायता कार्यक्रम) की सुविधा प्रदान करती है। **सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए घरेलू संसाधनों के प्रभावी एवं कुशल प्रयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अदिस अबाबा में अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग को बढ़ावा देने हेतु निर्धारित की गयी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में TIWB पहल एक सुदृढ़ कदम है।**

- TIWB पहल, "क्रियामूलक अधिगम (learning by doing)" दृष्टिकोण के माध्यम से विकासशील देशों के कर प्रशासकों को कर लेखा-परीक्षा सम्बन्धी ज्ञान और कौशल के हस्तांतरण को सुगम बनाती है। TIWB पहल के अंतर्गत अनुभवी कर लेखा परीक्षक, सहायता हेतु अनुरोध करने वाले देशों में स्थानीय कर अधिकारियों के साथ वर्तमान कर लेखा परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कर मुद्दों पर एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इस दौरान वे अपनी विशेषज्ञता और कौशल को साझा करते हैं।
- इस सन्दर्भ में एक संयुक्त OECD / UNDP TIWB सचिवालय पेरिस में स्थापित किया गया है जो विकासशील देशों में UNDP कार्यालयों के नेटवर्क द्वारा समर्थित है। यह सचिवालय प्रत्येक TIWB विशेषज्ञ का परिनियोजन करने के साथ ही इस परिनियोजन में एक समन्वयक तथा सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है।

35.B

- The FSDC was envisaged for performing two sets of core functions. First is to perform as an apex level forum to strengthen and institutionalize the mechanism for maintaining financial stability. Second is for enhancing inter-regulatory coordination and promoting financial sector development in the country.
- Composition of FSDC: The Chairman of the Council is the Finance Minister and its members include the heads of financial sector Regulators (RBI, SEBI, PFRDA, IRDA & FMC {now merged with SEBI}) Finance Secretary and/or Secretary, Department of Economic Affairs, Secretary, Department of Financial Services, and Chief Economic Adviser. The Council can invite experts to its meeting if required. The FSDC Secretariat is in the Department of Economic Affairs. But later in May 2018, the Council was expanded to include top bureaucrats related to Economic and Financial management. As a result, the total members are now increased to 12 besides the Chairman Finance Minister.
- The Council monitors macro-prudential supervision of the economy, including **functioning of large financial conglomerates**, **and addresses inter-regulatory coordination** and financial sector development issues. It also **focuses on financial literacy and financial inclusion**.
- **It is the Monetary Policy Committee which determines the policy interest rate required to achieve the inflation target. Hence only statement 2 is not correct.**
- वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद् (FSDC) की परिकल्पना निम्नलिखित दो प्रमुख कार्यों को संपादित करने के लिए की गई थी:
  - o प्रथम, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए तंत्र को मजबूत एवं संस्थागत बनाने हेतु एक उच्च स्तरीय मंच के रूप में कार्य करना तथा;
  - o द्वितीय, अंतर-नियामकीय समन्वय को बढ़ावा देने के साथ देश में वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना।
- **FSDC की संरचना:** इस परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और इसके सदस्यों में शामिल हैं- वित्तीय क्षेत्र के नियामकों यथा- RBI, SEBI, PFRDA, IRDA और FMC (जिसका अब SEBI में विलय कर दिया गया है) के प्रमुख, वित्त सचिव और/या आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार। आवश्यकता पड़ने पर परिषद, विशेषज्ञों को अपनी बैठक में आमंत्रित कर सकती है। FSDC सचिवालय, आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत आता है। किन्तु मई 2018 में, आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित शीर्ष नौकरशाहों को शामिल करने के लिए परिषद का विस्तार किया गया। परिणामस्वरूप, वित्त मंत्री (अध्यक्ष) के अतिरिक्त अब कुल सदस्यों की संख्या 12 हो गई है।
- **यह परिषद बड़े पैमाने पर कार्य करने वाले वित्तीय समूहों** सहित अर्थव्यवस्था की समष्टि स्तर पर विवेकपूर्ण ढंग से निगरानी करती है तथा साथ ही अंतर-नियामकीय समन्वय और वित्तीय क्षेत्र के विकास सम्बन्धी मुद्दों को संबोधित करती है। इसके साथ ही यह वित्तीय **साक्षरता और वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान केंद्रित करती है।**
- उल्लेखनीय है कि मुद्रास्फीति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दरों को निर्धारित करने का कार्य **मौद्रिक नीति समिति** करती है। **इसलिए केवल कथन 2 सही नहीं है।**

36.B

- Transfer pricing is the setting of the price for goods and services sold between controlled (or related) legal entities within an enterprise. For example, if a subsidiary company sells goods to a parent company, the cost of those goods paid by the parent to the subsidiary is the transfer price.
- In the context of transfer pricing mechanism, safe harbour refers to a situation when an eligible assessee has entered into an eligible international transaction and the transfer price declared by the assessee in respect of such transaction is accepted by the income-tax authorities. Thus, 'Safe Harbour' **means conditions in which income tax authorities shall accept the transfer price declared by the taxpayer.**
- ट्रांसफर प्राइसिंग किसी उद्यम के अंतर्गत आने वाली नियंत्रित (या सम्बन्धित) विधिक इकाईयों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं की उस कीमत के निर्धारण को कहते हैं जिस पर उनकी बिक्री की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सहायक कंपनी एक मूल कंपनी को वस्तुओं का विक्रय करती है, तो उन वस्तुओं के लिए मूल कंपनी द्वारा सहायक कंपनी को दी गयी कीमत ट्रांसफर प्राइसिंग कहलाती है।
- ट्रांसफर प्राइसिंग तंत्र के संदर्भ में सेफ हार्बर एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक पात्र कर निर्धारिती (assessee) एक पात्र अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में प्रवेश करता है और कर निर्धारिती द्वारा घोषित ट्रांसफर प्राइस को (ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन हेतु) आयकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार, **'सेफ हार्बर' से तात्पर्य उन शर्तों के समुच्चय से है जिन पर कर प्राधिकरण, करदाता द्वारा घोषित ट्रांसफर प्राइस को स्वीकार करते हैं।**
- **इसलिए विकल्प (b) सही उत्तर है।**

37.D

- As per the chart below, while Indian exports have steadily increased in the last decade, the year from 2013-14 to 2014-15 and 2014-15 to 2015-16 have witnessed a decline. **Hence, statement 1 is not correct.**
- As per the chart, the Indian trade balance hasn't witnessed a consistent trajectory. While it has widened from 2007-08 to 2012-13 (exception 2008-09 - 2009-10), it has since then narrowed down as of 2017-18 (exception 2013-14 - 2014-15). **Hence, statement 2 is not correct.**

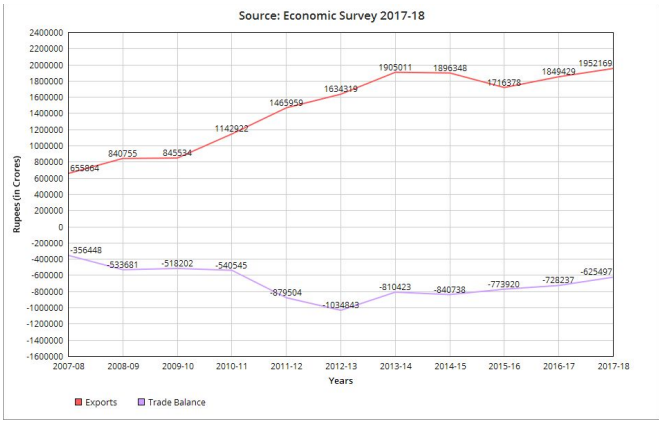

- नीचे दिए गए चार्ट से प्रदर्शित होता है कि यद्यपि पिछले दशक में भारतीय निर्यात में निरंतर वृद्धि हुई है, किन्तु 2013-14 से 2014-15 और 2014-15 से 2015-16 के मध्य गिरावट भी देखी गई है। **इसलिए कथन 1 सही नहीं है।**
- चार्ट के अनुसार, भारतीय व्यापार संतुलन का वक्र स्थिर नहीं रहा है। हालांकि इसमें 2007-08 से 2012-13 तक (2008-09 से 2009-10 इसका अपवाद था) निरंतर वृद्धि हुई है, किन्तु पुनः 2017-18 (अपवाद स्वरूप 2013-14 से 2014-15) में यह कम हो गया है। **इसलिए कथन 2 सही नहीं है।**

38.D

- The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) was established to help build a new, post-Cold War era in Central and Eastern Europe. Uniquely for a development bank, the EBRD has a political mandate in that it assists only those countries 'committed to and applying the principles of multi-party democracy and pluralism'.
- **India became the 69th member (shareholder) of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)**, paving the way for more joint investment with Indian companies across the bank's regions of operation. **China**, France, Germany, Israel, Italy, Japan, **the Russian Federation**, the United Kingdom and the **United States of America**, as well as the European Union, are some of its financing members.
- Following are some of the countries that are recipients of EBRD funds: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Egypt, Greece, Hungary, Jordan, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Mongolia, Russia, Tajikistan, Tunisia, Turkey, Turkmenistan etc.
- **यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक** (यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट: EBRD) की स्थापना का उद्देश्य शीत-युद्ध के उपरांत मध्य एवं पूर्वी यूरोप का पुनर्गठन करना था। EBRD को राजनीतिक जनादेश प्राप्त है जो किसी भी डेवलपमेंट बैंक के लिए अद्वितीय है, जिसके अंतर्गत यह केवल उन्हीं देशों को सहायता प्रदान करता है जो 'बहु-दलीय लोकतंत्र और बहुलवाद के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हैं एवं उनका कार्यान्वयन' सुनिश्चित करते हैं।
- **भारत EBRD का 69वां सदस्य (शेयरधारक) बना,** जिससे बैंक के सभी परिचालनात्मक क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों द्वारा किये जाने वाले संयुक्त निवेश में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। **चीन**, फ्रांस, जर्मनी, इज़राइल, इटली, जापान, **रूस**, यूनाइटेड किंगडम और **संयुक्त राज्य अमेरिका** तथा यूरोपीय संघ, इसका वित्तपोषण करने वाले कुछ सदस्य हैं।
- इसके अतिरिक्त EBRD द्वारा वित्तपोषण प्राप्तकर्ता देशों में आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, मिस्र, ग्रीस, हंगरी, जॉर्डन, कज़ाखस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मंगोलिया, रूस, ताजिकिस्तान, ट्यूनीशिया, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान इत्यादि सम्मिलित हैं।

39.A

- **Statement 1 is correct:** The real effective exchange rate (REER) is the weighted average of a country's currency in relation to an index or basket of other major currencies, adjusted for the effects of inflation. The weights are determined by comparing the relative trade balance of a country's currency against each country within the index. This exchange rate is used to determine an individual country's currency value relative to the other major currencies in the index, such as the U.S. dollar, Japanese yen and the euro.
- **Statement 2 is not correct:** The value of REER is an important indicator for deciding the movement of exchange rate. When the index of REER goes above 100 mark (with index of REER in base year =100), **then the domestic currency is overvalued.** Hence, domestic prices are too high and domestic producers are not competitive. On the other hand, if the REER is less than 100, then the domestic currency is undervalued. Domestic prices are low by international standards and domestic producers are competitive.

- **Statement 3 is not correct: The Indices of Real Effective Exchange rate in India are released by Reserve Bank of India.** The bank provides REER using the Consumer Price Index.
- **कथन 1 सही है:** वास्तविक प्रभावी विनिमय दर' (REER) वस्तुतः मुद्रास्फीति के प्रभावों को समायोजित करने के लिए अन्य प्रमुख मुद्राओं के एक सूचकांक या बास्केट के संबंध में एक देश की मुद्रा का भारित औसत है। इस सूचकांक के भीतर प्रत्येक देश के विरुद्ध एक देश की मुद्रा के सापेक्ष व्यापार संतुलन की तुलना करके किसी मुद्रा के भारित औसत का निर्धारण किया जाता है। इस विनिमय दर का उपयोग इस सूचकांक में अन्य प्रमुख मुद्राओं, जैसे- अमेरिकी डॉलर, जापानी येन और यूरो के सापेक्ष एक देश की मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
- **कथन 2 सही नहीं है:** REER का मान विनिमय दर के उतार-चढ़ाव का निर्धारण करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। जब REER का सूचकांक 100 अंक से ऊपर चला जाता है (आधार वर्ष में REER सूचकांक का मान= 100), **तब घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन (overvalued) होता है।** इसलिए, घरेलू कीमतें बहुत उच्च हो जाती हैं और ऐसे में घरेलू उत्पादक प्रतिस्पर्धात्मक नहीं होते। दूसरी ओर, यदि REER 100 से कम होती है, तो घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन (undervalued) होता है। घरेलू कीमतें अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में कम हो जाती हैं और ऐसे में घरेलू उत्पादक प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं।
- **कथन 3 सही नहीं है: भारत में REER सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए जाते हैं।** RBI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करके REER सूचकांक प्रदान करता है।

40.C

- The concept of effective Revenue deficit was introduced in the **Union Budget 2011-12.** It was later on given statutory status by an amendment to the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act by the Finance Act, 2012.
- Effective Revenue Deficit is the difference between revenue deficit and grants for creation of capital assets. The concept of 'Grants for creation of capital assets' was introduced in the FRBM Act through the amendment in 2012. It defines grants for creation of capital assets as **grants-in-aid given by the Central Government to State governments, autonomous bodies, local bodies and other scheme implementing agencies for creation of capital assets which are owned by these entities.**
- प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा **केंद्रीय बजट 2011-12 में** प्रस्तुत की गई थी। बाद में इसे वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम में एक संशोधन के माध्यम से सांविधिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था।
- प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे तथा पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु दिए गए अनुदानों के मध्य का अंतर होता है। "पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान" की अवधारणा वर्ष 2012 में FRBM अधिनियम में एक संशोधन के द्वारा अंतःस्थापित की गई थी। यह अधिनियम 'पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों' को '**राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों और योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली अन्य एजेंसियों को उनके स्वामित्व वाली पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदानों' के रूप में परिभाषित करता है।**

41.A

- **MSF scheme is provided by RBI by which the banks can borrow overnight upto 1 per cent of their net demand and time liabilities (NDTL)** i.e. 1 per cent of the aggregate deposits and other liabilities of the banks.
- MSF, being a penal rate, is always **fixed above the repo rate.** The MSF would be the **last resort for banks once they exhaust all borrowing options** including the liquidity adjustment facility by pledging government securities, where the rates are lower in comparison with the MSF. The MSF would be a penal rate for banks and the banks can borrow funds by pledging government securities within the limits of the statutory liquidity ratio. The scheme has been introduced by RBI with the main aim of reducing volatility in the overnight lending rates in the inter-bank market and to enable smooth monetary transmission in the financial system.
- चूंकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (सीमान्त स्थायी सुविधा) दर एक दंडात्मक दर है, अतः इसे सदैव रेपो रेट से ऊपर रखा जाता है। MSF, बैंकों के लिए ऋण प्राप्ति के सारे विकल्प समाप्त हो जाने पर (सरकारी प्रतिभूतियों के बदले प्राप्त LAF, जहाँ MSF की तुलना में दरें कम होती हैं, सहित) ऋण प्राप्ति का **अंतिम उपाय होती है**। बैंकों के लिए MSF एक दंडात्मक दर होती है और बैंक सांविधिक तरलता अनुपात (SLR-Statutory Liquidity Ratio) की सीमा के भीतर सरकारी प्रतिभूतियों के बदले ऋण प्राप्त कर सकते हैं। RBI द्वारा इस योजना को अंतर-बैंक बाजार में ओवरनाइट (रात भर के लिए दिए जाने वाले) ऋण की दरों की अस्थिरता को कम करने और वित्तीय तंत्र में मौद्रिक संचरण को सुचारु रूप से चलाने के मुख्य उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था।
- **RBI द्वारा शुरू की गयी MSF योजना के अंतर्गत बैंक रात भर के लिए अपनी शुद्ध मांग एवं सावधि देयताओं (नेट डिमांड एवं टाइम लायबिलिटीज़: NDTL) के 1% तक** यानि कि बैंक की कुल जमा एवं अन्य देयताओं के 1% तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

42.B

- **Trade Receivables Discounting System (TReDS) is an initiative of Reserve Bank of India to facilitate MSME receivables payments from corporates.** MSME sellers, corporate buyers and financiers – both banks and non-bank (NBFC factors) will be direct participants in the TReDS.
- The TReDS will provide the platform to bring these participants together for facilitating uploading, accepting, discounting, trading and settlement of the invoices / bills of MSMEs. The bankers of MSMEs and corporate buyers may be provided access to the system, where necessary, for obtaining information on the portfolio of discounted invoices / bills of respective clients. The TReDS may tie up with necessary technology providers, system integrators and entities providing dematerialisation services for providing its services.

- **ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) कॉर्पोरेट्स द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) को किये जाने वाले भुगतान को सुविधाजनक बनाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की एक पहल है।** MSME विक्रेता, कॉर्पोरेट खरीददार तथा वित्तदाता- बैंक एवं गैर-बैंकिंग संस्थान (NBFCs) दोनों, TReDS में प्रत्यक्ष प्रतिभागी होंगे।
- TReDS इन प्रतिभागियों को MSME के इनवॉइस / बिलों की अपलोडिंग, स्वीकृति, डिस्काउन्टिंग, व्यापार तथा निपटारे को सुविधाजनक बनाने हेतु एक साथ लाने के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म प्रदान करेगा। अपने संबंधित ग्राहकों के डिस्काउंटेड इनवॉइस (discounted invoice)/बिलों पोर्टफोलियो से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु (जब भी आवश्यक हो) MSMEs के बैंकरों एवं कॉर्पोरेट खरीददारों को इस व्यवस्था तक पहुँच प्रदान की जाएगी। TReDS अपनी सेवाएं प्रदान करने हेतु डीमैटीरियलाइज़ेशन (भौतिक शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरुप में बदलना) सेवाएं देने वाले आवश्यक प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, सिस्टम इंटीग्रेटर्स तथा संस्थाओं के साथ स्वयं को जोड़ सकता है।

43.A

- The government has the power to supersede Central Board of Directors of Reserve Bank of India (RBI). It can supersede Central Board if in its opinion, the Central Board has failed to carry out any of the obligations imposed under the Reserve Bank of India Act, 1934. **Hence, option (a) is not correct.**
- The RBI has the sole right to issue bank notes. The minting of Coins falls under the exclusive domain of the government under the of the Coinage Act, 2011. However, the responsibility for **circulation** for both Banknotes and Coins is entrusted with the RBI. **Hence, option (b) is correct.**
- The government can issue directions to RBI from time to time only on grounds of public interest. As per Section 7 of the RBI act - 1934, the government can from time to time give such directions to the RBI as it may, after consultation with the governor of the bank, **considered necessary in the public interest**. **Hence, option (c) is correct.**
- The Monetary Policy Committee of India is a committee of the Reserve Bank of India that is responsible for fixing the benchmark interest rate in India. **It comprises six members - three officials of the Reserve Bank of India and three external members nominated by the Government of India.** The Governor of Reserve Bank of India is the chairperson *ex-officio* of the committee. Thus, it has representation from both RBI and government. Decisions are taken by majority with the Governor having the casting vote in case of a tie. **Hence, option (d) is correct.**
- सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India: RBI) के केंद्रीय निदेशक बोर्ड (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) की शक्तियां अपने हाथ में ले सकती है। यदि सरकार के विचार में, केंद्रीय बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 के तहत अधिरोपित दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है तो वह केंद्रीय बोर्ड को प्रतिस्थापित कर सकती है। **इसलिए, विकल्प (a) सही नहीं है।**
- बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार RBI के पास है। सिक्के ढालने का अधिकार, सिक्का अधिनियम, 2011 के अंतर्गत सरकार के अनन्य परिक्षेत्र में आता है। हालांकि, बैंक नोट्स और सिक्के दोनों के परिचालन का उत्तरदायित्व RBI को सौंपा गया है। **इसलिए, विकल्प (b) सही है।**
- सरकार केवल लोक हित के आधार पर समय-समय पर RBI के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकती है। RBI अधिनियम, 1934 की धारा 7 के अनुसार, सरकार समय-समय पर RBI के गवर्नर से परामर्श के पश्चात् RBI को ऐसे दिशा-निर्देश जारी कर सकती है जिन्हें वह लोक हित में आवश्यक समझती है। **इसलिए, विकल्प (c) सही है।**
- भारत की मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक की एक समिति है जो भारत में बेंचमार्क ब्याज दर के निर्धारण हेतु उत्तरदायी है। **इसमें छह सदस्य शामिल हैं - RBI के तीन अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामित तीन बाह्य सदस्य।** भारतीय रिज़र्व बैंक का गवर्नर इस समिति का अध्यक्ष होता है। इस प्रकार इसमें RBI और सरकार दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं तथा मतों की बराबरी की स्थिति में गवर्नर के पास *कास्टिंग वोट* (मतदान करने) का अधिकार प्राप्त होता है। **इसलिए, विकल्प (d) सही है।**

44.B

- **Statement 1 is not correct:** Index of Industrial Production (IIP) is a composite indicator which measures the quantum of changes in the industrial production in an economy and captures the general level of industrial activity in the country. It is expressed in terms of an index number which measures the short term changes in the volume of production of a basket of industrial products during a given period with respect to the base period. Industrial production for the purpose of IIP is divided into three sectors, i.e, Mining, Manufacturing, and Electricity. In 'Sectoral' classification, relative weights of Manufacturing, Mining, and Electricity are 75.5%, 14.2%, and 10.3% respectively.
- **Statement 2 is correct:** Index of Industrial Production is compiled and published every month by Central Statistics Office (CSO) of the Ministry of Statistics and Programme Implementation with a time lag of six weeks from the reference month.
- **कथन 1 सही नहीं है**: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production: IIP) एक समग्र संकेतक है जो अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन में परिवर्तन की मात्रा की माप करता है और देश में औद्योगिक गतिविधि के सामान्य स्तर को दर्शाता है। इसे एक इंडेक्स नंबर (सूचकांक संख्या) के रूप में व्यक्त किया जाता है जो आधार अवधि के संदर्भ में किसी प्रदत्त अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के समूह के उत्पादन की मात्रा में अल्पावधिक परिवर्तनों की माप करता है। IIP के उद्देश्य से औद्योगिक उत्पादन को तीन क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है, यथा- खनन, विनिर्माण,और विद्युत्। 'क्षेत्रकवार' वर्गीकरण में, विनिर्माण, खनन और विद्युत् का सापेक्षिक भार क्रमश: 75.5%, 14.2%, और 10.3% हैं।
- **कथन 2 सही है:** औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा संदर्भ माह से छह सप्ताह के समय के साथ प्रत्येक माह संकलित और प्रकाशित किया जाता है।

45.A

- Engel's Law is an economic theory introduced in 1857 by Ernst Engel, a German statistician, stating that **the percentage of income allocated for food purchases decreases as income rises**. As a household's income increases, the percentage of income spent on food decreases while the proportion spent on other goods (such as luxury goods) increases. As the "Engel coefficient" increases, the country is by nature poorer; conversely a low Engel coefficient indicates a higher standard of living. For example, recently it was **reported that Engel's coefficient of China's urban areas fell from 39.4 percent to 35 percent from 2000 to 2013 pointing to the rise in living standards.**
- जर्मन सांख्यिकीविद एर्नस्ट एंजेल द्वारा वर्ष 1857 में प्रस्तुत आर्थिक सिद्धांत, एंजेल का नियम कहलाता है। इसके अनुसार "**आय में वृद्धि के साथ खाद्य पदार्थों के क्रय हेतु आवंटित आय का प्रतिशत घटता जाता है।**" अर्थात् जैसे ही एक परिवार की आय में वृद्धि होती है, भोजन पर व्यय की गयी आय का प्रतिशत घट जाता है जबकि अन्य वस्तुओं (जैसे- विलासिता की वस्तुएं) पर किए गए व्यय के अनुपात में बढ़ोत्तरी हो जाती है। जैसे-जैसे एंजेल गुणांक में वृद्धि होती जाती है, देश स्वभावतः निर्धन होता जाता है, इसके विपरीत एक निम्न एंजेल गुणांक जीवनयापन के उच्च स्तर की ओर संकेत करता है। उदाहरणार्थ- हाल ही में यह **सूचना प्राप्त हुई थी कि चीन के नगरीय क्षेत्रों में एंजेल गुणांक में वर्ष 2000 से वर्ष 2013 के मध्य 39.4% से 35% तक गिरावट दर्ज की गई थी। यह गिरावट निर्वाह स्तरों में वृद्धि की ओर संकेत करती है।**

46.D

- Any reduction in the rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit should have been passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices. However, it has been the experience of many countries that when GST was introduced there has been a marked increase in inflation and the prices of the commodities. **The Authority's main function is to ensure that traders are not realizing an unfair profit by charging high price from consumers in the name of GST. Hence statement 1 is correct.**
- The responsibility of NAA is to examine and check such profiteering activities and recommend punitive actions including cancellation of Registration. The process of application of complaint by a consumer to the National Anti-Profiteering Authority is depicted below.
- DG Anti-profiteering is the investigating-arm in the anti-profiteering mechanism. It can summon the interested parties or make inquiry or call for the relevant documents for the investigation. It can take help from technical expert in the due course of investigation. **Hence statement 2 is correct.**
- A consumer can directly file the complaint to NAA without having to go through the National Consumer Disputes Redressal Commission. **Hence statement 3 is correct.**
- वस्तुओं या सेवाओं की किसी भी आपूर्ति पर कर की दर में कोई कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्तकर्ता को कीमतों में समान कमी के माध्यम से दिया जाना चाहिए। हालांकि, कई देशों में यह देखा गया है कि जब वहां GST लागू किया गया तब वहां पर मुद्रास्फीति और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुयी। इस **प्राधिकरण का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापारी उपभोक्ताओं से GST के नाम पर अधिक कीमत आरोपित करके अनुचित लाभ ना प्राप्त कर पाएं। इसलिए कथन 1 सही है।**
- राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण की ज़िम्मेदारी ऐसी लाभकारी गतिविधियों की जांच एवं निरीक्षण करना तथा साथ ही पंजीकरण रद्द करने सहित दंड की सिफारिश करना है। उपभोक्ता द्वारा राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण में शिकायत सम्बन्धी आवेदन की प्रक्रिया का वर्णन चित्र में किया गया है।
- मुनाफाखोरी विरोधी तंत्र में मुनाफाखोरी की जांच 'मुनाफाखोरी विरोधी महानिदेशक' करता है। यह जांच के लिए इच्छुक पक्षों को समन जारी कर सकता है या उनकी जांच कर सकता है अथवा सम्बंधित दस्तावेजों की मांग कर सकता है। यह जांच के दौरान तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ले सकता है। इसलिए कथन 2 सही है।
- एक उपभोक्ता, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास जाये बिना सीधे NAA में शिकायत दर्ज करवा सकता है। **इसलिए कथन 3 सही है।**

47.A

- One of the leading budgeting technique followed in India at present is the outcome budgeting or outcome-based budgeting. It is practised by most of the Ministries while preparing their budget details and submitting it to the Ministry of Finance for the preparation of the annual budget towards the end of February. **Hence statement 1 is correct.**
- The Outcome Budget of all Ministries is combined into one single document and brought out by the Ministry of Finance in collaboration with the NITI Aayog. **Hence statement 2 is correct.**
- An interesting feature of outcome-based budgeting is that the outcomes of programmes are measured not just in terms of Rupees but also in terms of physical units like Kilowatt of energy produced or tonnes of steel produced. Also, outcomes are expressed in terms of qualitative targets and achievements to make the technique more comprehensive. **Hence statement 3 is not correct.**
- **कथन 1 सही है।** वर्तमान में भारत में अपनाई जाने वाली प्रमुख बजट तकनीकों में से एक आउटकम बजट या परिणाम-आधारित बजट है। अधिकांश मंत्रालयों द्वारा अपना बजट विवरण तैयार करते समय एवं फरवरी के अंत में वार्षिक बजट तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय को इसे भेजते समय इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

- सभी मंत्रालयों का आउटकम बजट एक ही दस्तावेज में संयोजित किया जाता है और नीति आयोग के सहयोग से वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। **इसलिए कथन 2 सही है।**
- आउटकम बजट की एक रुचिकर विशेषता यह है कि कार्यक्रमों के परिणामों को न केवल रुपयों के सन्दर्भों में अपितु भौतिक इकाइयों जैसे कि उत्पादित ऊर्जा के किलोवाट या उत्पादित किए गए इस्पात (स्टील) के टन के संदर्भों में भी मापा जाता है। इसके अतिरिक्त, तकनीक को अधिक व्यापक बनाने के लिए गुणात्मक लक्ष्यों और उपलब्धियों के सन्दर्भों में भी परिणाम व्यक्त किए जाते हैं। **इसलिए कथन 3 सही नहीं है।**

48.A

- The balance of payments (BoP) record the transactions in goods, services and assets **between residents of a country with the rest of the world** for a specified time period typically a year. It can be divided into two parts - Current account and capital account.
- Balance of Payments-
  - Current account
    - It records exports and imports in goods and services and transfer payments. Trade in services denoted as invisible trade includes both factor income (payment for inputs-investment income, that is, the interest, profits and dividends on our assets abroad minus the income foreigners earn on assets they own in India) and non-factor income (shipping, banking, insurance, tourism, software services, etc.). Transfer payments are receipts which the residents of a country receive 'for free', without having to make any present or future payments in return. They consist of **remittances,** gifts and grants. They could be official or private.
  - Capital Account - The capital account records all international purchases andsales of assets such as money, stocks, bonds, etc. It consists of-
    - External Assistance
    - External Commercial Borrowings
    - **Short-term credit**
    - Banking Capital
    - **Non-Resident Deposits**
    - Foreign Investment - FDI, Portfolio
    - Other Flows
  - Errors and Omission
- भुगतान संतुलन (BoP) में **किसी देश के निवासियों द्वारा शेष विश्व के साथ** किसी विशिष्ट समयावधि (सामान्यतया एक वर्ष) में किये गए वस्तुओं, सेवाओं और संपत्तियों के लेन-देन को शामिल किया जाता है। इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है- चालू खाता और पूँजी खाता।
- **भुगतान संतुलन:**

o **चालू खाता**

- इसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयातों एवं निर्यातों तथा अंतरण भुगतानों को शामिल किया जाता है। अदृश्य व्यापार के रूप में माने जाने वाले सेवाओं के व्यापार में कारक आय (आगत हेतु भुगतान-निवेश आय अर्थात् विदेशों में हमारी संपत्तियों पर ब्याज, लाभ और लाभांश में से विदेशियों द्वारा भारत में उनकी अपनी सम्पत्ति पर अर्जित आय को घटा कर प्राप्त हुई आय) और गैर-कारक आय (जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाएं आदि) दोनों शामिल हैं। अंतरण भुगतान वे प्राप्तियाँ होती हैं जिन्हें किसी देश के निवासी वर्तमान या भविष्य में किसी भी प्रकार का भुगतान किए बिना प्रतिफल में 'नि:शुल्क' प्राप्त करते हैं। इनमें **विप्रेषित धन,** उपहार और अनुदान शामिल होते हैं। ये सरकारी अथवा निजी हो सकते हैं।

o **पूँजी खाता-** पूँजी खाते में धन, शेयर, बंधपत्र (बॉन्ड) इत्यादि जैसी परिसम्पत्तियों की समस्त अंतरराष्ट्रीय खरीद एवं बिक्री को दर्ज किया जाता है। इसमें शामिल हैं :-

- विदेशी सहायता
- विदेशी वाणिज्यिक उधारियां
- **अल्पावधिक ऋण**
- बैंकिंग पूँजी
- **अनिवासी जमाएं**
- विदेशी निवेश - FDI, पोर्टफोलियो
- अन्य लेन-देन

o भूल-चूक (Errors and Omissions)

o **रिज़र्व चैंज (ये पूँजी या चालू खाते के भाग का सृजन नहीं करते। ये भुगतान संतुलन के तहत एक पृथक वर्ग हैं।)**

इसलिए विकल्प (a) सही उत्तर है।

49.A

- Millets are collective of a number of different small-grained cereal grasses.
- Based on their sizes, two main groups of millets are:
  - Major millets: Sorghum (jowar) and Pearl millet (Bajra)

○ Small millets represented by six species, namely finger millet (ragi), little millet, kodo millet, foxtail millet, barnyard millet and proso millet, representing the area grown in that order.

● Of late, the classification is also an indication of the area under these crops. Millets are widely used in African and Asian countries. Majorly cultivated in the semi-arid tropical regions of Africa and Asia, around 97 per cent of the world's overall millet production happens in these regions. India is the world's largest producer. **Hence statement 2 is correct.**

● The government decided to declare the Year 2018 as "National Year of Millets" to boost production of the nutrient-rich millets and the sunrise agri industry (an emerging industry with bright growth potential) involved in it. **Hence statement 1 is correct.**

● Government announces minimum support prices (MSPs) for millets like Sorghum (jowar), Pearl millet (Bajra) and finger millet (ragi). **Hence statement 3 is not correct.**

● मोटे अनाज को छोटे दाने वाली खाद्यान्न के समूह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

● आकार के आधार पर, मोटे खाद्यान्नों को दो समूहों में विभाजित किया जाता है:

o प्रमुख अनाज: सोरघम (ज्वार), बाजरा (पर्ल मिलेट)

o छोटे अनाजों में कुल छह प्रजातियाँ शामिल हैं: फिंगर मिलेट (रागी), लिटिल मिलेट, कोड़ो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट तथा प्रोसो मिलेट (उल्लेखनीय है कि इन फसलों को उगाने का क्षेत्रफल भी इसी क्रम में है)

● वर्तमान में, उपर्युक्त वर्गीकरण इन फसलों के तहत कृषि क्षेत्र को भी इंगित करता है। अफ्रीकी एवं एशियाई देशों में मोटे अनाजों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसकी कृषि मुख्यतः अफ्रीका एवं एशिया के अर्द्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ विश्व के कुल मोटे अनाज उत्पादन का लगभग 97 प्रतिशत उत्पादित होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, यहाँ प्रति वर्ष लगभग 11 मिलियन टन मोटे अनाजों का उत्पादन होता है, जो विश्व उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत है। भारत के कुल मोटे अनाज उत्पादन में लगभग दो-तिहाई बाजरे (पर्ल मिलेट) का उत्पादन होता है। **इसलिए कथन 2 सही है।**

● सरकार ने पोषक तत्वों से समृद्ध मोटे अनाजों एवं सनराइज कृषि उद्योग (उज्ज्वल विकास क्षमता वाला एक उभरता हुआ उद्योग) के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष **2018 को "मोटे अनाजों के राष्ट्रीय वर्ष"** के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया। **इसलिए कथन 1 सही है।**

● सरकार ने ज्वार, बाजरा एवं रागी जैसे मोटे अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा की है। **इसलिए कथन 3 सही नहीं है।**

50.A

● During the sixth BRICS Summit in Fortaleza (2014), the leaders signed the Agreement establishing the New Development Bank (NDB) also known as BRICS bank. In the Fortaleza Declaration, the leaders stressed that the NDB will strengthen cooperation among BRICS and will supplement the efforts of multilateral and regional financial institutions for global development, thus contributing to collective commitments for achieving the goal of strong, sustainable and balanced growth. **Hence statement 1 is correct.**

● The headquarters of the Bank is located at Shanghai. **Hence statement 2 is not correct.**

● The Bank shall have an initial authorized capital of US$ 100 billion. The initial subscribed capital is US$ 50 billion, **equally shared among founding members**. The first chair of the Board of Governors is from Russia. The first chair of the Board of Directors is from Brazil. The first President of the Bank is from India. **Hence statement 3 is not correct.**

● **फोर्टालेजा (2014) में** आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, सदस्य देशों के नेताओं ने **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)** की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। फोर्टालेजा घोषणा में, नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि NDB ब्रिक्स देशों के मध्य सहयोग को सुदृढ़ करेगा और वैश्विक विकास के लिए बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों का अनुपूरक होगा, इस प्रकार यह सशक्त, सतत तथा संतुलित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सामूहिक प्रतिबद्धताओं में योगदान करता है। **इसलिए कथन 1 सही है।**

● NDB का मुख्यालय **शंघाई** (चीन) में स्थित है। **इसलिए कथन 2 सही नहीं है।**

● न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास 100 बिलियन डॉलर की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी (initial authorized capital) होगी। इसकी प्रारंभिक अभिदत्त पूंजी (initial subscribed capital) 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जिसे **सभी संस्थापक सदस्यों के मध्य समान रूप से साझा किया गया है**। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की प्रथम अध्यक्षता रूस तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रथम अध्यक्षता ब्राजील द्वारा की जाएगी। बैंक का प्रथम अध्यक्ष भारत से होगा। **इसलिए कथन 3 सही नहीं है।**

51.C

● Micro-irrigation is the slow application of water above, or below the soil by surface drip, subsurface drip, bubbler and micro-sprinkler systems, thereby increasing the yield and productivity of crops. The task force on micro-irrigation had estimated potential of 69.5 million hectares under micro-irrigation, whereas the area covered so far is only about 10 million hectares.

● **Statement 1 is correct:** To promote mirco irrigation, the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved an initial Corpus of Rs.5,000 crore for setting up of a dedicated "Micro Irrigation Fund" (MIF) with NABARD under Pradhan Mantri Krishi SinchayeeYojana (PMKSY).

● **Statement 2 is not correct:** NABARD will provide this amount to states on concessional rate of interest to promote micro-irrigation. The lending rate under MIF has been proposed at 3% lower than the cost of raising the fund by NABARD. The fund will facilitate States to mobilise resources for their initiatives, including additional (top up subsidy) in the implementation of PMKSY-PDMC (Per Drop More Crop) to achieve the annual target of about 2 million hectares per year during the remaining period of 14th Finance Commission. This is not a refinancing fund.

- **Statement 3 is correct:** Farmers Producers Organization (FPO)/Cooperatives/State Level Agencies can also access the funds with state government guarantee or equivalent collateral. Farmers Co-operatives may access this fund for innovative cluster based community irrigation projects.
- सूक्ष्म सिंचाई (Micro-irrigation) में सतही ड्रिप, उपसतही ड्रिप, बब्लर (bubbler) और सूक्ष्म फव्वारा पद्धति द्वारा मृदा की सतह या सतह के नीचे जल को धीरे-धीरे छोड़ा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप फसलों की उपज और उत्पादकता में वृद्धि होती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर गठित कार्य बल द्वारा 69.5 मिलियन हेक्टेयर की सूक्ष्म सिंचाई क्षमता का अनुमान लगाया गया था, जबकि अभी तक केवल 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि को ही सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है।
- **कथन 1 सही है:** सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत नाबार्ड के साथ एक समर्पित "सूक्ष्म सिंचाई कोष" (MIF) की स्थापना हेतु 5,000 करोड़ रूपए की आरंभिक राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- **कथन 2 सही नहीं है:** सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने हेतु नाबार्ड इस राशि को रियायती ब्याज दर पर राज्यों को उपलब्ध करवाएगा। MIF के तहत ब्याज दर नाबार्ड द्वारा फंड एकत्र करने की लागत की तुलना में 3% कम प्रस्तावित की गयी है। इस कोष से 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि के दौरान करीब 2 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष के वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्यों को PMKSY-PDMC (प्रति बूंद अधिक फसल) के कार्यान्वयन में अतिरिक्त टॉप अप सब्सिडी सहित अपनी पहलों के लिए संसाधन जुटाने में सहायता प्राप्त होगी। यह पुनर्वित्तीयन कोष नहीं है।
- **कथन 3 सही है:** किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)/सहकारी समितियों/ राज्य स्तर की एजेंसियों की भी राज्य सरकार की गारंटी के साथ कोषों तक पहुंच हो सकती है अथवा वे समान भागीदार हो सकते हैं। नवोन्मेष क्लस्टर आधारित सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं हेतु कृषक सहकारी समितियाँ भी MIF के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

52. D

53.C

54.D

55.D.

56.C

57. B

58.C

- **The Incremental Capital Output Ratio (ICOR) indicate additional unit of capital needed to produce an additional unit of output. It assesses the marginal amount of investment capital necessary for an entity to generate the next unit of production.**
- Capital output ratio has an important role in economic planning. If the government targets an economic growth of 10% for next year and the capital output ratio in India is 3. Then, to realize 10% growth, investment should be increased to 30% (10 x3). Capital output ratio thus explain the relationship between level of investment and the corresponding economic growth.
- ICOR shows current efficiency of capital whereas Capital Output Ratio covers historical efficiency of capital.
-
- A lower capital output ratio shows that only low level of investment is needed to produce a given growth rate in the economy. Lower capital output ratio shows that capital is very productive or efficient. Anything, which is component of production process, may reduce the ICOR if it's productivity improves. If the labour productivity improves, it will help maximize output on the invested capital.
- **Hence both the statements are correct.**
- **वृद्धिशील पूँजी उत्पाद अनुपात (Incremental Capital Output Ratio: ICOR) उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने हेतु आवश्यक पूँजी की एक अतिरिक्त इकाई को दर्शाता है। यह किसी निकाय के लिए उत्पादन की अगली इकाई उत्पन्न करने हेतु आवश्यक निवेश पूंजी की सीमांत राशि का आकलन करता है।**
- आर्थिक नियोजन में पूंजी उत्पाद अनुपात की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि सरकार अगले वर्ष के लिए 10% की आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखती है और भारत में पूंजी उत्पाद अनुपात 3 हो, तो 10% की वृद्धि के लिए निवेश को 30% (10 x3) तक बढ़ाना होगा। इस प्रकार पूंजी उत्पाद अनुपात निवेश के स्तर और संबंधित आर्थिक विकास के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है।
- ICOR पूँजी की वर्तमान क्षमता को दर्शाता है जबकि पूँजी उत्पाद अनुपात पूँजी की पारम्परिक क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- पूँजी उत्पाद अनुपात का निम्न होना यह दर्शाता है कि उस अर्थव्यवस्था में एक वांछित वृद्धि दर को उत्पन्न या प्राप्त करने हेतु केवल एक निम्न स्तर के निवेश की आवश्यकता है। निम्न पूँजी उत्पाद अनुपात यह दर्शाता है कि पूँजी अत्यधिक उत्पादक या सक्षम है। उत्पादन प्रक्रिया के किसी भी घटक की उत्पादकता में सुधार से ICOR में कमी आ सकती है। यदि श्रम उत्पादकता बढ़ती है तो यह निवेशित पूँजी के सापेक्ष उत्पादन में वृद्धि करेगी।
- **इसलिए दोनों कथन सही हैं।**

59.D

- India had recently signed the currency swap agreements with Governments of Japan and UAE.
- Currency Swap is such a pact between two countries that allows trading in their own currency and payments to import and export trade at pre-determined exchange rate without bringing in a third benchmark currency like the US dollars. The agreement consists of

swapping principal and interest payments on a loan made in one currency for principal and interest payments of a loan of equal value in another currency.

- Currency swaps have the following main uses:
  - To convert a liability in one currency into a liability in another currency.
  - To convert an investment (asset) in one currency to an investment in another currency
  - To promote bilateral trade and facilitate direct investment between the two countries in respective local currencies.
  - **To hedge against (reduce exposure to) exchange rate fluctuations.**
  - **To secure cheaper debt (by borrowing at the best available rate regardless of currency and then swapping for debt in the desired currency using a back-to-back-loan). Thus, helping to bring down the cost of funds for Indian companies while borrowing from the foreign market.**
  -
- **One distinct advantage of the swap is greater recognition of currencies involved in such transactions. Therefore, currency swap in the rupee with our counterparts will help in the internationalization of the rupee.**
- Such mechanisms do provide a stable regime to importer and exporter helping them to concentrate on factors other than currency risk.
- **Swap arrangements reduce or eliminate convertibility risk and transfer risk.**
- हाल ही में भारत ने जापान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स (currency swap agreements) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- मुद्रा विनिमय दो देशों के मध्य एक संधि है जो अमेरिकी डॉलर जैसी किसी तीसरी बेंचमार्क मुद्रा के उपयोग बिना पूर्व-निर्धारित विनिमय दर पर उनकी अपनी मुद्रा में व्यापार करने तथा आयात और निर्यात व्यापार हेतु भुगतान करने की अनुमति प्रदान करता है। इस संधि में एक मुद्रा में लिए गए ऋण के मूलधन तथा ब्याज के भुगतान का दूसरी मुद्रा में उसी मूल्य के ऋण के मूलधन तथा ब्याज के साथ अदला-बदली का प्रावधान भी शामिल होता है।
- **करेंसी स्वैप के निम्नलिखित मुख्य उपयोग हैं:**

o किसी एक मुद्रा में देयता को किसी अन्य मुद्रा में देयता में परिवर्तित करना।
o किसी एक मुद्रा में निवेश (परिसंपत्ति) को दूसरी मुद्रा में निवेश में परिवर्तित करना।
o द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना और दोनों देशों के बीच संबंधित स्थानीय मुद्राओं में प्रत्यक्ष निवेश को संभव बनाना।
o **विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से संरक्षण प्रदान करना (जोखिम को कम करना)।**
o **सस्ता ऋण प्राप्त करना (मुद्रा की परवाह किए बिना सर्वोत्तम उपलब्ध दर पर उधार लेकर और फिर बैक-टू-बैक-लोन का उपयोग करके वांछित मुद्रा में ऋण के लिए स्वैप करना)। इस प्रकार यह भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी बाज़ार से उधार लेने में ऋण की लागत को कम करने में सहायता करेगा।**

- **स्वैप का एक अलग लाभ यह होगा कि ऐसे लेन-देन में शामिल मुद्राओं को अधिक मान्यता प्राप्त होगी। इसलिए अपने समकक्षों के साथ रुपये में 'करेंसी स्वैप' किया जाना रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण में सहायक होगा।**
- इस प्रकार के तंत्र आयातक और निर्यातक को एक प्रणालीगत स्थिरता प्रदान करते हैं। इससे उन्हें मुद्रा जोखिम के अलावा अन्य कारकों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता प्राप्त होती है।
- **स्वैप व्यवस्था परिवर्तनीयता जोखिम और हस्तांतरण जोखिम को कम करती है या समाप्त करती है।**

60.B

- The textile industry is facing a shortage of skilled workers and provides many opportunities for unemployed youth in the country who are trained in the sector. To address the issue, **Central government of India has launched Scheme for Capacity Building in Textile Sector (SCBTS) and named it SAMARTH Scheme.**
- **The broad objective of the new scheme is to skill the youth for gainful and sustainable employment in the textile sector covering the entire value chain of textiles, excluding spinning and weaving.**
- Other objectives:
  - to provide demand-driven, placement oriented skilling programme to incentivize the efforts of the industry in creating jobs in the organized textile and related sectors;
  - to promote skilling and skill up-gradation in the traditional sectors through respective sectoral divisions/organizations of the Ministry of Textile; and
  - to provide livelihood to all sections of the society across the country.
- वस्त्र उद्योग कुशल कार्मिकों की कमी का सामना कर रहा है और यह देश के उन बेरोजगार युवाओं को अनेक अवसर उपलब्ध कराता है जो इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हों। इस मुद्दे के समाधान के लिए भारत की केंद्र सरकार ने **वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (Scheme for Capacity Building in Textile Sector: SCBTS)** का शुभारंभ किया और इसे **समर्थ (SAMARTH) योजना** नाम दिया।
- नई योजना का व्यापक उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में लाभकारी और स्थायी रोजगार के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करना है। इसमें कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्र क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला शामिल किया गया है।
- अन्य उद्देश्य:

o संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मांग-संचालित, रोज़गार-उन्मुख कौशल कार्यक्रम उपलब्ध कराना;
o वस्त्र मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय प्रभागों/संगठनों के माध्यम से पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल और कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना; तथा
o देश में समाज के सभी वर्गों को आजीविका प्रदान करना।

61.B

• Treasury Bills (T-Bills) are government bonds or debt securities with maturity of less than a year. T- bills are issued to meet short-term mismatches in receipts and expenditure.

• **Commercial Paper (CP) is an unsecured money market instrument issued in the form of a promissory note. CPs are short-term instruments and the maturity period varies from seven days to up to one year. CPs can be issued by corporates, primary dealers, and financial institutions.**

• A certificate of deposit (CD) is a savings certificate with a fixed maturity date and specified fixed interest rate that can be issued in any denomination aside from minimum investment requirements. A CD restricts access to the funds until the maturity date of the investment. CDs are generally issued by commercial banks.

• A repurchase agreement, or repo for short, is a type of short-term loan much used in the money markets, whereby the seller of a security agrees to buy it back at a specified price and time. The seller pays an interest rate, called the repo rate, when buying back the securities.

● ट्रेजरी बिल (टी-बिल) एक वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि वाले सरकारी बॉन्ड या ऋण प्रतिभूतियां होती हैं। T- बिल वे बिल होते हैं जिन्हें आय एवं व्यय में अल्पकालिक अंतराल को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है।

● **वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper: CP) एक गैर-जमानती मुद्रा बाजार लिखत होता है जिसे प्रॉमिसरी नोट (P नोट) के रूप में जारी किया जाता है। CP अल्पकालिक लिखत होते हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि सात दिनों से लेकर एक वर्ष तक होती है। वाणिज्यिक पत्र कॉर्पोरेट कंपनियों, प्राथमिक डीलरों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किये जा सकते हैं।**

● जमा-प्रमाण पत्र (certificate of deposit: CD) एक निश्चित परिपक्वता तिथि और निर्दिष्ट निश्चित ब्याज दर के साथ ऐसे बचत प्रमाण पत्र होते हैं जिन्हें न्यूनतम निवेश आवश्यकताओं को पूरा करते हुए किसी भी मूल्यवर्ग में जारी किया जा सकता है। एक जमा-प्रमाण पत्र निवेश की परिपक्वता तिथि तक धन के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। जमा-प्रमाण पत्र आम तौर पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किये जाते हैं।

● एक पुनर्खरीद समझौता (repurchase agreement) या संक्षेप में रेपो एक प्रकार का अल्पकालिक ऋण होता है जिसका मुद्रा बाजारों में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। इसमें प्रतिभूति का विक्रेता एक निर्धारित मूल्य और समय पर इसे वापस खरीदने हेतु सहमत होता है। विक्रेता प्रतिभूतियों को वापस खरीदते समय एक निश्चित ब्याज दर पर भुगतान करता है जिसे रेपो रेट कहा जाता है।

62.D

● The reserves with the RBI accumulate due to several factors. First is its **income from three sources:**
○ **interest on government bonds held by RBI for conducting open market operations;**
○ fees from government market borrowing programme;
○ and i**ncome from investment in foreign currency assets.**
● Second source is **earnings retained after giving dividends to government.**
● Third source is **revaluation of foreign assets and gold.** The increase in RBI's capital base is largely driven by the increased accumulation of forex reserves in the post-crisis era. At present, it is about 28.3% of RBI's balance sheet (Rs 9.6 lakh crore) and Usha Thorat Panel recommended to bring down to 18%.
● Hence all are the components of RBI to build its reserves.
● **RBI** का रिज़र्व अनेक कारकों के चलते संचित होता है। प्रथम कारक, निम्नलिखित तीन स्त्रोतों से प्राप्त इसकी आय है:
o खुले बाजार की क्रियाओं (Open Market Operations: OMO) के संचालन हेतु धारित सरकारी बंधपत्रों पर ब्याज;
o सरकारी बाजार उधारी कार्यक्रम से प्राप्त शुल्क; तथा
o विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में निवेश से प्राप्त आय।
● दूसरा स्त्रोत सरकार को लाभांश प्रदान करने के पश्चात् प्रतिधारित उपार्जन है।
● तीसरा स्त्रोत विदेशी परिसंपत्तियों और स्वर्ण का पुनर्मूल्यांकन है। RBI के पूँजी आधार में वृद्धि वस्तुतः संकट पश्चात् युग में विदेशी मुद्रा भंडारों के वर्धित संचय के कारण है।
● वर्तमान में यह रिज़र्व RBI के बैलेंस शीट (9.6 लाख करोड़ रूपए) का 28.3% है तथा उषा थोराट पैनल ने इसे कम कर 18% तक लाने की अनुशंसा की है।
● इसलिए सभी विकल्प RBI के रिज़र्व के सृजक हैं।

63.A

● **Statement 1 is correct: The monetary value of an asset decreases over time due to use, wear and tear or obsolescence.** This decrease is measured as depreciation. Depreciation is thus an annual allowance for wear and tear of a capital good. In other words it is the cost of the good divided by number of years of its useful life. Depreciation, i.e. a decrease in an asset's value, may be caused by a

number of other factors as well such as unfavorable market conditions, etc. Machinery, equipment, currency are some examples of assets that are likely to depreciate over a specific period of time (So depreciation is flow variable).

- **Statement 2 is correct:** Net investment means new addition to capital stock or new capital formation in an economy, which is expressed as:
- **Net Investment = Gross investment – Depreciation.** So when there is high level of depreciation, then major portion of gross investment will go into maintenence. So there will be less new capital formation i.e less amount of net investment.
- **Statement 3 is not correct:** Depreciation does not take into account unexpected or sudden destruction or disuse of capital as can happen with **accidents, natural calamities or other such extraneous circumsta**nces.
- **कथन 1 सही है: किसी परिसम्पत्ति का मौद्रिक मूल्य कुछ समय पश्चात् उसके उपयोग, टूट-फूट या अप्रचलन के कारण कम हो जाता है।** इस गिरावट का मापन मूल्यह्रास (अथवा ह्रास) के रूप में किया जाता है। इस प्रकार मूल्यह्रास किसी पूंजीगत वस्तु के टूट-फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। दूसरे शब्दों में, यह वस्तु के उपयोग के वर्षों की संख्या से लागत में भाग देने पर प्राप्त होता है। मूल्यह्रास (अर्थात् किसी परिसम्पत्ति के मूल्य में गिरावट) प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों आदि जैसे अन्य अनेक कारकों के परिणामस्वरूप भी हो सकती है। मशीनें, उपकरण और मुद्रा आदि परिसम्पत्तियों के कुछ उदाहरण हैं जिनमे संभवत: एक विशिष्ट समयावधि में मूल्यह्रास हो सकता है। इसलिए मूल्यह्रास एक प्रवाह परिवर्त (flow variable) है।
- **कथन 2 सही है:** निवल निवेश का अर्थ है- पूँजी स्टॉक में नवीन परिवर्धन अथवा किसी अर्थव्यवस्था में नव पूँजी निर्माण, जिसे निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है:
  - **निवल निवेश = सकल निवेश - मूल्यह्रास।** इस प्रकार जब मूल्यह्रास का स्तर उच्च होता है तब सकल निवेश का प्रमुख हिस्सा रखरखाव में खर्च हो जाता है। इसलिए पूँजी निर्माण कम होगा (अर्थात् निवल निवेश की अल्प मात्रा)।
- **कथन 3 सही नहीं है:** मूल्यह्रास में **दुर्घटनाओं, प्राकृतिक विपदाओं या ऐसी अन्य बाह्य परिस्थितियों के कारण** पूंजी के अप्रत्याशित या अकस्मात विनाश या अप्रयोग को शामिल नहीं किया जाता है।

64.A

- **Statement 1 and statement 2 are correct:** At its core, blockchain is an open, decentralized ledger that records transactions between two parties in a permanent way without needing third-party authentication. This creates an extremely efficient process and will dramatically reduce the cost of transactions.
- Blockchain was the technology behind the Bitcoin. Other than Bitcoin, applications of Blockchain technology include Financial Services, Smart Property, Internet-of-Things (IoT), Smart Contracts etc.
- **Statement 3 is not correct:** It is the World Bank that has launched bond-i (blockchain operated new debt instrument), the world's first bond to be created, allocated, transferred and managed through its life cycle using distributed ledger technology i.e. Blockchain Technology. The World Bank mandated Commonwealth Bank of Australia (CBA) as arranger for the bond
- **कथन 1 और 2 सही हैं:** ब्लॉकचेन मूलतः एक खुला और विकेन्द्रित खाता-बही (ledger) होता है जिसमें तीसरे पक्ष के सत्यापन की आवश्यकता के बिना एक स्थायी रीति से दो पक्षों के मध्य होने वाले लेन-देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। यह एक अत्यंत कुशल प्रक्रिया का सृजन करता है तथा यह विभिन्न लेन-देन की लागत को प्रभावशाली रूप से कम करेगा।
- बिटकॉइन ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर ही आधारित है। बिटकॉइन के अतिरिक्त ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं, स्मार्ट प्रॉपर्टी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इत्यादि भी शामिल हैं।
- **कथन 3 सही नहीं है:** वर्ल्ड बैंक द्वारा bond-i (ब्लॉकचेन ऑपरेटेड न्यू डेट इंस्ट्रूमेंट) लॉन्च किया गया है। यह वितरित खाता-बही (ledger) प्रौद्योगिकी अर्थात् ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इसके लाइफ साइकिल (जीवन चक्र) के दौरान सृजित, आवंटित, हस्तांतरित और प्रबंधित होने वाला विश्व का प्रथम बॉन्ड है। विश्व बैंक ने कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया (CBA) को बॉन्ड के प्रबंधक के रूप में अधिदेशित किया है।

65.C

- The impossible trinity, also called the Mundell-Fleming trilemma or simply the trilemma, expresses the limited options available to countries in setting monetary policy. **According to this theory, a country cannot achieve the free flow of capital, a fixed exchange rate and independent monetary policy simultaneously.** By pursuing any two of these options, it necessarily closes off the third.
- According to the trilemma model, a country has three options. It can
  - A - set a fixed exchange rate between its currency and another while allowing capital to flow freely across its borders,
  - B - allow capital to flow freely and set its own monetary policy, or
  - C - set its own monetary policy and maintain a fixed exchange rate.
- 'इम्पॉसिबल ट्रिनिटी' (Impossible Trinity) को मुंडेल-फ्लेमिंग ट्राईलेमा अथवा केवल ट्राईलेमा भी कहा जाता है। यह मौद्रिक नीति को निर्धारित करते समय देशों के समक्ष उपलब्ध सीमित विकल्पों को व्यक्त करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, कोई देश पूंजी का मुक्त प्रवाह, स्थिर विनिमय दर और स्वतंत्र मौद्रिक नीति को एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता है। इन विकल्पों में से किन्ही भी दो विकल्पों का अनुसरण करने पर तीसरे विकल्प का मार्ग अनिवार्यत: बंद हो जाता है।
- ट्राईलेमा मॉडल के अनुसार, किसी देश के समक्ष निम्नलिखित तीन विकल्प मौजूद होते हैं:

A- वह पूंजी को अपनी सीमाओं में स्वतंत्र प्रवाह की अनुमति प्रदान करते हुए अपनी मुद्रा एवं दूसरी मुद्रा के मध्य एक स्थिर विनिमय दर निर्धारित कर सकता है।
B- वह पूंजी के स्वतंत्र प्रवाह की अनुमति दे सकता है तथा स्वयं की मौद्रिक नीति निर्धारित कर सकता है।

C- वह स्वयं की मौद्रिक नीति निर्धारित कर सकता है और एक स्थिर विनिमय दर बनाए रख सकता है।

66.B

- Recently, Blackstone Group along with Embassy Office Parks has filed India's first and Asia's largest prospectus for Real Estate Investment Trust (REIT).
- **Statement 1 is correct:** A REITs works very much like a mutual fund. It pools funds from a number of investors and invests them in rent-generating properties.REITs are investment vehicles that own, operate and manage a portfolio of income-generating properties for regular returns. These are usually commercial properties (offices, shopping centres, hotels etc.) that generate rental income.
- **Statement 2 is correct:** REITS are regulated by the securities market regulator in India- Securities and Exchange Board of India (SEBI). In September 2014, SEBI notified the SEBI (Real Estate Investment trusts) Regulations, 2014 for providing a framework for registration and regulation of REITs in India.
- **Statement 3 is not correct:** Markets regulator Securities and Exchange Board of India (Sebi) has been easing rules to make REITs more attractive to investors. In January 2017, the markets regulator permitted mutual funds to invest in REITs. The Reserve Bank of India (RBI) further allowed banks to invest in such investment trusts following a request from the markets regulator. Another such trust for investment is InvITs(infrastructure investment trusts). InvITs are trusts that manage income-generating infrastructure assets, typically offering investors regular yield and a liquid method of investing in infrastructure projects.
- हाल ही में, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स के साथ ब्लैकस्टोन ग्रुप ने रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) के लिए भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा प्रॉस्पेक्टस दर्ज किया है।
- **कथन 1 सही है**। REIT बहुत हद तक म्यूचुअल फंड के समान कार्य करता है। यह बड़ी संख्या में निवेशकों से फंड एकत्रित करके उसे किराया सृजित करने वाली संपत्तियों में निवेश करता हैं। REIT निवेश के ऐसे साधन होते हैं जो नियमित रिटर्न के लिए आय-सृजक संपत्तियों के पोर्टफोलियो का स्वामित्व, संचालन एवं प्रबंधन करते हैं। ये सामान्यतः वाणिज्यिक सम्पत्तियां (कार्यालय, शॉपिंग सेंटर, होटल आदि) होती हैं जो किराये के रूप में आय का सृजन (rental income) करती हैं।
- **कथन 2 सही है।** REITS को भारत में प्रतिभूति बाजार नियामक अर्थात् भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा विनियमित किया जाता है। सितंबर 2014 में, सेबी ने भारत में REIT के पंजीकरण और विनियमन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल एस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 को अधिसूचित किया।
- **कथन 3 सही नहीं है।** बाजार विनियामक SEBI द्वारा निवेशकों के लिए REIT को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु नियमों को सुगम बनाया गया है। जनवरी 2017 में, बाजार विनियामक ने म्यूचुअल फंड को REIT में निवेश करने हेतु अनुमति प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बाजार विनियामक के अनुरोध के पश्चात **बैंकों को इस प्रकार के निवेश ट्रस्टों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है।** निवेश के लिए इस प्रकार का एक अन्य ट्रस्ट InvITs (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) है। InvITs वे ट्रस्ट होते हैं जो आय सृजित करने वाली अवसंरचना परिसंपत्ति का प्रबंधन करते हैं, ये विशेष रूप से निवेशकों को नियमित रिटर्न और अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश की अधिक तरलीकृत पद्धति प्रदान करते हैं।

67.D

- **Statement 1 is not correct:** For the past five years (Starting 2013-14); While there has been a consistent increase in gross tax revenue as a percentage of Gross Domestic Product, there has been a decline from year 2013-14 to 2014-15.
- **Statement 2 is not correct:** For the past five years (Starting 2013-14); While the direct tax revenue has been consistently more than fifty percent to gross tax revenue, it dropped to below fifty (49.5%) for the year 2016-17.

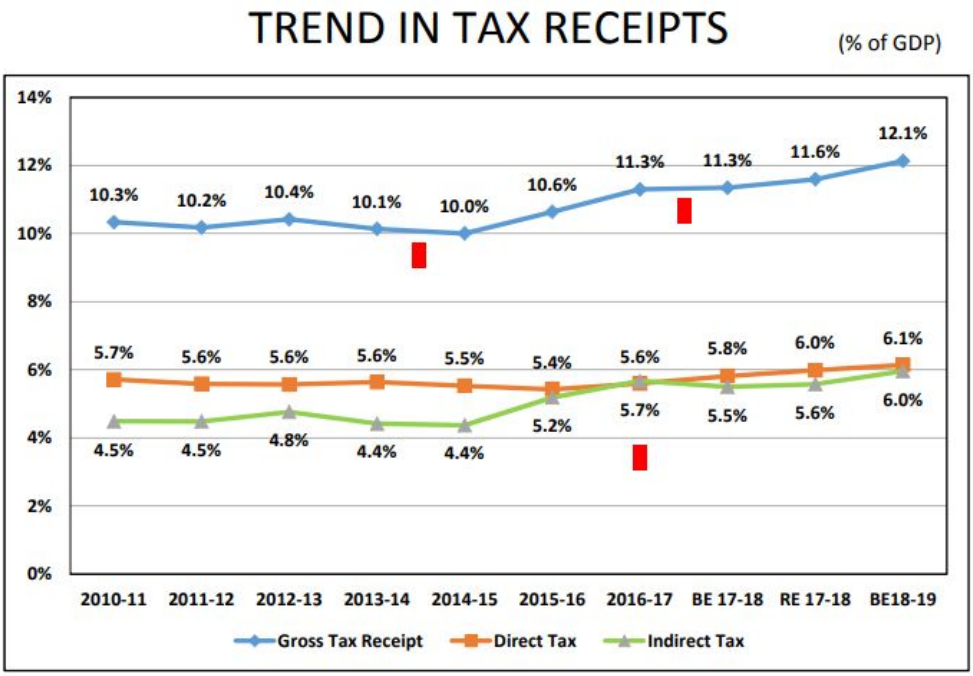

Source : Union Budget 2018-19

- **कथन 1 सही नहीं है:** यद्यपि विगत पांच वर्षो की अवधि (2013-14 से प्रारंभ) में सामान्यतः सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व में निरंतर वृद्धि हुई है, किन्तु 2013-14 से 2014-15 के मध्य इसमें गिरावट दर्ज की गई थी।
- **कथन 2 सही नहीं है:** यद्यपि विगत पांच वर्षो की अवधि (2013-14 से प्रारंभ) में सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर राजस्व का योगदान सामान्यतः पचास प्रतिशत से अधिक रहा है, परन्तु वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह पचास प्रतिशत से नीचे (49.5%) पहुँच गया था।

68.B

- **The Paris Club is an informal group of creditor nations whose objective is to find workable solutions to payment problems faced by debtor nations**. The Paris Club has 19 permanent members, including most of the western European and Scandinavian nations, the United States of America, the United Kingdom and Japan.
- The Paris Club stresses the informal nature of its existence and deems itself a "non-institution." As an informal group, it has no official statutes and no formal inception date, although its first meeting with a debtor nation was in 1956, with Argentina.
- Singapore issues are the list of the subject that were tabled by the Western states mainly US and EU in the WTO conference in the year 1996.
- **पेरिस क्लब ऋणदाता राष्ट्रों का एक अनौपचारिक समूह है, जिसका उद्देश्य ऋणी राष्ट्रों के समक्ष आने वाली भुगतान संबंधी समस्याओं के लिए व्यवहारिक समाधानों की खोज करना है।** पेरिस क्लब में 19 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें अधिकांश पश्चिमी यूरोपीय और स्कैंडिनेवियाई राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जापान शामिल हैं।
- पेरिस क्लब अपने अस्तित्व की अनौपचारिक प्रकृति पर बल देता है और स्वयं को एक "गैर-संस्थान" के रूप में मानता है। एक अनौपचारिक समूह के रूप में इसका कोई आधिकारिक विधान और कोई औपचारिक स्थापना तिथि नहीं है। हालाँकि ऋणी राष्ट्रों के साथ इसकी प्रथम बैठक वर्ष 1956 में अर्जेंटीना में आयोजित हुई थी।
- सिंगापुर मुद्दे उन विषयों की सूची हैं जो वर्ष 1996 में विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन में पश्चिमी राष्ट्रों (मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ) द्वारा प्रस्तुत किये गये थे।

69.A

- **Statement 1 is correct:** Disinvestment or divestiture refers to the government selling or liquidating its assets or stakes in PSE (public sector enterprise), while strategic Disinvestment is the sale of a substantial portion of the Government shareholding of a central public sector enterprise (CPSE) of up to 50%, or such higher percentage along with transfer of management control. Disinvestment proceeds can help the government fund its fiscal deficit.
- **Statement 2 is correct:** The Department for investment and public asset management (DIPAM) under Ministry of finance is the nodal agency for disinvestment.

- **Statement 3 is not correct:** The proceeds from disinvestment of Central Public Sector Enterprises are channelized into National Investment Fund (NIF), not into National Investment and Infrastructure Fund (NIIF). NIF was constituted in November 2005.
- **कथन 1 सही है।** विनिवेश या डिवेस्टिचर सरकार द्वारा किसी PSE (सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम) में उसकी परिसंपत्ति या हिस्सेदारी की बिक्री अथवा परिसमापन किये जाने को संदर्भित करता है; जबकि रणनीतिक विनिवेश सरकार द्वारा किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE) में 50% तक की या ऐसी ही किसी बड़ी हस्सेदारी की बिक्री और साथ ही प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण किये जाने को संदर्भित करता है। विनिवेश की कार्यवाही से सरकार को राजकोषीय घाटे की भरपाई करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
- **कथन 2 सही है।** वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) विनिवेश के लिए नोडल एजेंसी है।
- **कथन 3 सही नहीं है।** केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय राष्ट्रीय निवेश कोष (NIF) में जमा की जाती है, न कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) में। NIF का गठन नवंबर 2005 में किया गया था।

70.C

- The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana was announced in the Union Interim Budget 2019. T**he Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi will provide assured income to small and marginal farmers.** Under the scheme PM-Kisan all Small and Marginal farmers (SMF) families having cultivable land upto two hectares will be provided income support of Rs.6000/- per year directly into their bank accounts, in three equal installments. The complete expenditure of Rs 75000 crore for the scheme will be borne by the Union Government in 2019-20.
- Over 12 crore farmer families will be benefitted under the scheme. The scheme is being implemented with effect from December 2018. Guidelines for States for implementation of the scheme:
  - The selection of eligible small farmer families under the scheme will be undertaken by the State Governments.
  - The necessary details such as bank account details will be provided on the online portal so that the first installment of the benefits can be transferred to the eligible families.
  - The States will prepare database of eligible beneficiary landholder farmer families in the villages capturing the Name, Age, Gender, Category (SC/ST) , Aadhaar Number/ Driving Licence/Voters' ID Card/ NREGA Job Card, Bank Account Number, IFSC Code.
  - Though mobile number is not mandatory, but it may be noted when available so that the information related to transfer of benefit can be communicated.
  - States/UTs shall ensure that there is no duplication of the payment transferred to eligible families.
  - Speedy settlement in case of wrong or incomplete bank details of the beneficiary should be ensured.
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की घोषणा केंद्रीय अंतरिम बजट 2019 में की गई है। **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता प्रदान की जाएगी।** इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान (SMF) परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यह आय सहायता तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी जाएगी। 2019-20 में योजना के लिए 75000 करोड़ रुपये के संपूर्ण व्यय को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होंगे। यह योजना दिसंबर 2018 से लागू की गयी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यों के लिए जारी दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं :

o योजना के तहत पात्र छोटे किसान परिवारों का चयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।
o आवश्यक विवरण, जैसे बैंक खाते का विवरण, ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदान किया जाएगा ताकि लाभ की पहली किस्त पात्र परिवारों को हस्तांतरित की जा सके।
o गांवों के पात्र लाभार्थी भूस्वामी किसानों के परिवारों का डेटाबेस राज्य द्वारा तैयार किया जायेगा। इसके तहत पात्र लाभार्थी का नाम, आयु, लिंग, श्रेणी (SC / ST), आधार नंबर / ड्राइविंग लाइसेंस / मतदाता पहचान-पत्र / मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड आदि शामिल होगा।
o हालांकि इसके लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य नहीं है, लेकिन उपलब्ध होने पर इसे नोट किया जा सकता है ताकि लाभ के हस्तांतरण से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
o राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि पात्र परिवारों को हस्तांतरित किये गए भुगतान में किसी प्रकार का कोई दोहराव न हो।
o लाभार्थी के गलत या अपूर्ण बैंक विवरण के मामले में शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

71.A

- N.K Singh committee was formed to review the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003. **It has nothing to do with the Monetary policy which is under the ambit of the RBI**. The FRBM Review Committee (Chairperson: Mr. N.K. Singh) submitted its report in January 2017
- The Committee suggested using debt as the primary target for fiscal policy. Debt to GDP ratio of 60% should be targeted with a 40% limit for the centre and 20% limit for the states**. It noted that the majority of the countries that have adopted fiscal rules have targeted debt to GDP ratio of 60%. The targeted debt to GDP ratio should be achieved by 2023. Hence, statement 1 is correct.**
- **Fiscal Council:** The Committee proposed to create an autonomous Fiscal Council with a Chairperson and two members appointed by the centre. To maintain its independence, it proposed a non-renewable four-year term for the Chairperson and members.

Further, **these people should not be employees in the central or state governments at the time of appointment. Hence statement 2 is not correct.**

- The Committee noted that under the FRBM Act, the government can deviate from the targets in case of a national calamity, national security or other exceptional circumstances notified by it. Further, **the government may be allowed to deviate from the specified targets upon the advice of the Fiscal Council in the following circumstances:** (i) considerations of national security, war, national calamities and collapse of agriculture affecting output and incomes, (ii) structural reforms in the economy resulting in fiscal implications, or (iii) decline in real output growth of at least 3% below the average of the previous four quarters. These deviations cannot be more than 0.5% of GDP in a year.
- **It did not provide any targeted inflation rate. Under the Monetary Policy Framework Agreement, the RBI will be responsible for containing inflation targets at 4% (with a standard deviation of 2%) in the medium term. Hence statement 3 is not correct.**
- एन. के. सिंह समिति का गठन राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की समीक्षा हेतु किया गया था। **इसका RBI के क्षेत्राधिकार में शामिल मौद्रिक नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है।** FRBM समीक्षा समिति (अध्यक्ष: श्री एन.के. सिंह) ने जनवरी 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- समिति ने ऋण को राजकोषीय नीति के प्राथमिक लक्ष्य के रूप में निर्धारित करने का सुझाव दिया। ऋण- GDP अनुपात 60% (केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20% की सीमा निर्धारण के साथ) की अनुशंसा की गयी। **यह उल्लेखनीय है, कि राजकोषीय नियमों को अपनाने वाले अधिकांश देशों ने ऋण-GDP अनुपात को 60% तक निर्धारित किया है। ऋण-GDP अनुपात को 2023 तक प्राप्त किए जाने की अनुशंसा की गयी है। अतः कथन 1 सही है।**
- **राजकोषीय परिषद :** समिति ने केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और दो सदस्यों के साथ एक स्वायत्त राजकोषीय परिषद के गठन का सुझाव दिया। परिषद की स्वायत्तता को सुनिश्चित करने हेतु इसके अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चार वर्ष का कार्यकाल प्रस्तावित किया गया है, साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, **नियुक्ति के समय इन्हें (अर्थात् अध्यक्ष व सदस्यों को) केंद्र या राज्य सरकारों की सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- समिति ने उल्लेख किया कि FRBM अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय सुरक्षा या इसके अंतर्गत अधिसूचित अन्य असाधारण परिस्थितियों में सरकार को लक्ष्य प्राप्त करने में कुछ छूट प्रदान की जा सकती है। **इसके अतिरिक्त, सरकार को निम्नलिखित परिस्थितियों में राजकोषीय परिषद की सलाह पर निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के मामले में छूट प्रदान की जा सकती है:** (i) उत्पादन एवं आय को प्रभावित करने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, राष्ट्रीय आपदाओं और कृषि क्षेत्र के ह्रास की स्थिति में (ii) राजकोषीय निहितार्थ के परिणामस्वरूप संरचनात्मक अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु, या (iii) वास्तविक उत्पादन वृद्धि में विगत चार तिमाहियों के औसत से कम से कम 3% की गिरावट की स्थिति में। यह छूट एक वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% से अधिक नहीं हो सकती है।
- **इसके द्वारा किसी लक्षित मुद्रास्फीति दर की अनुशंसा नहीं की गयी है। मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते के तहत निर्धारित किया गया है कि, RBI मध्यम अवधि में मुद्रास्फीति लक्ष्य को 4% तक (2% के मानक विचलन के साथ) सीमित रखने के लिए उत्तरदायी होगा। अतः कथन 3 सही नहीं है।**

72.D

- The Balance of Payment (BoP) is the summary/account sheet that shows the cash flow between India and the rest of the world. BoP is made up of two parts: Current account and Capital account. (As per IMF definition, three parts: Current Account + Capital account+ Financial Account)
- **Current Account Components:**
  - Import and Export of goods and services (invisible)
    - Depreciation is the lowering of the value of a country's currency within a market exchange rate system with respect to a foreign reference currency or currency basket.
    - By depreciation, the prices of Indian exports in terms of foreign currency (say dollar) will likely fall. This will likely cause an increase in quantity demanded of Indian exports. As a result, Indian exports will likely increase, narrowing down the current account deficit. **Hence, option 1 is correct.**
    - Since India is dependent on import of crude oil, it forms a significant portion of the country's current account. Any decline in crude oil prices will reduce our import bill, which in turn help to narrow down the current account deficit and vice versa. **Hence, option 3 is correct.**
  - Income from abroad (interest, dividends paid on Indian investor's FDI, FII in USA etc.)
  - Transfer:
    - Gift, **remittances from NRI** to their families etc. A higher amount of remittances helps in lowering the current account deficit. **Hence option 2 is correct.**
- **Capital Account Components:**
  - Foreign investment in India (FDI, FII, ADR, direct purchase of land, assets).
  - External commercial borrowing, external assistance etc.
- **Recent trends** in Current Account are given below.
  - 4.7 percent of GDP in 2012-13

- 1.7 percent of GDP in 2013-14
- 1.3 percent of GDP in 2014-15
- 1.1 percent of GDP in 2015-16
- 0.7 percent of GDP in 2016-17
- 0.6 percent of GDP in 2016-17
- 1.9 percent of GDP in 2017-18

● भुगतान संतुलन (BoP) खाता विवरण/खाता पत्रक है जो भारत और शेष विश्व के मध्य नकदी प्रवाह को प्रदर्शित करता है। BoP दो खातों अर्थात् चालू खाते और पूंजी खाते से मिलकर बना है (IMF की परिभाषा के अनुसार इसके तहत तीन खाते शामिल हैं: चालू खाता + पूंजी खाता + वित्तीय खाता)।

● **चालू खाते के घटक:**

o वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात और निर्यात (अदृश्य)

● अवमूल्यन से तात्पर्य किसी बाजार विनिमय दर प्रणाली में एक देश की मुद्रा का मूल्य संदर्भित विदेशी मुद्रा या करेंसी बास्केट के मूल्य की तुलना में कम होना है।

● अवमूल्यन की स्थिति में विदेशी मुद्रा (डॉलर) के संदर्भ में भारतीय निर्यात के मूल्य में कमी होगी। इसके परिणामस्वरूप भारतीय निर्यात की मात्रा में वृद्धि हो सकती है, जिससे चालू खाता घाटे में कमी होगी। **इसलिए, विकल्प 1 सही है।**

● चूंकि भारत कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है, इसलिए यह देश के चालू खाते का एक महत्वपूर्ण भाग है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से आयात बिल में कमी होगी, जिससे चालू खाते के घाटे को कम करने में सहायता प्राप्त होगी। **इसलिए, विकल्प 3 सही है।**

o विदेश से प्राप्त आय (ब्याज, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि में भारतीय निवेशक के FDI, FII पर प्रदत्त लाभांश)

o अंतरण:

● उपहार, NRIs द्वारा अपने परिवारों को विप्रेषण (remittances) आदि। विप्रेषण, चालू खाता घाटे को कम करने में सहायक होता है। **इसलिए विकल्प 2 सही है।**

● **पूंजी खाते के घटक:**

o भारत में विदेशी निवेश (FDI, FII, ADR, संपत्ति, भूमि की प्रत्यक्ष खरीद)।

o बाह्य वाणिज्यिक उधार, बाह्य सहायता आदि।

● चालू खाते की नवीनतम प्रवृत्ति निम्नलिखित है:

o 2012-13 में GDP का 4.7 प्रतिशत

o 2013-14 में GDP का 1.7 प्रतिशत

o 2014-15 में GDP का 1.3 प्रतिशत

o 2015-16 में GDP का 1.1 प्रतिशत

o 2016-17 में GDP का 0.7 प्रतिशत

o 2016-17 में GDP का 0.6 प्रतिशत

o 2017-18 में GDP का 1.9 प्रतिशत

73.C

● **The Government has announced a mega pension yojana namely 'Pradhan Mantri Shram-Yogi Maandhan' for the unorganised sector workers with monthly income upto Rs. 15,000.**

● **Only the workers between the age group of 18-40 years can join this scheme.**

● The Government will deposit equal matching share in the pension account of the worker every month till the age of 60 years.

● Under the scheme, an assured monthly pension of Rs 3,000 per month will be provided to workers in the unorganised sector after 60 years of age.

● **सरकार ने असंगठित क्षेत्र के 15,000 रुपए की मासिक आय वाले कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन नामक एक मेगा पेंशन योजना की घोषणा की है।**

● केवल 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के कामगार (कर्मचारी) ही इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

● 60 वर्ष की आयु तक प्रत्येक माह कामगार के पेंशन खाते में सरकार द्वारा निर्धारित अंशदान (लाभार्थी की आयु के आधार पर) जमा किया जाएगा।

● इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

74.D

● **Credit default swaps (CDS) are a type of insurance against default risk by a particular company.** The company is called the reference entity and the default is called credit event. It is a contract between two parties, called a protection buyer and protection seller. Under the contract, the protection buyer is compensated for any loss emanating from a credit event in a reference instrument. In return, the protection buyer makes periodic payments to the protection seller.

● In the event of a default, the buyer receives the face value of the bond or loan from the protection seller. From the seller's perspective, CDS provides a source of easy money if there is no credit event. CDS was introduced by JP Morgan.

- **क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप (CDS) किसी विशिष्ट कंपनी के डिफ़ॉल्ट जोखिम के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा है।** इसके तहत कंपनी को संदर्भ इकाई (reference entity) और डिफ़ॉल्ट को क्रेडिट इवेंट कहा जाता है। यह दो पक्षों यथा- संरक्षण क्रेता (protection buyer) और संरक्षण विक्रेता (protection seller) के मध्य किया गया एक अनुबंध है। इस अनुबंध के तहत संरक्षण क्रेता (protection buyer) को एक रिफरेन्स इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत किसी भी क्रेडिट इवेंट द्वारा होने वाली क्षति पूर्ति हेतु मुआवजा दिया जाता है। इसके प्रत्युत्तर में संरक्षण खरीददार द्वारा संरक्षण विक्रेता को आवधिक भुगतान किया जाता है।
- डिफॉल्ट की स्थिति में क्रेता द्वारा संरक्षण विक्रेता से बॉन्ड या ऋण का अंकित मूल्य (face value) प्राप्त किया जाता है। विक्रेता के दृष्टिकोण से CDS सुलभ धनराशि का स्रोत (कोई क्रेडिट इवेंट न होने की स्थिति में) प्रदान करता है। CDS को जेपी मॉर्गन द्वारा प्रारंभ किया गया था।

75.A

- Consumer Welfare Fund is created under section 57 of the CGST Act,2017.
- **Undue benefits made by businesses under the GST law have to be deposited in the fund, in case it cannot be passed on the identified recipient.**
- As per the GST anti-profiteering rules, the Centre and the 'concerned state' has been empowered to equally share the amount deposited by erring businesses in the consumer welfare fund. 'Concerned state' would mean the state where the anti-profiteering authority has passed its order against the businesses.
- The proceeds from the consumer welfare fund, constituted under Goods and Services Tax (GST), can be given as a grant to the Centre and state governments as well as regulatory authorities.
- उपभोक्ता कल्याण कोष का गठन केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 की धारा 57 के तहत किया गया है।
- **GST कानून के तहत प्रावधान है कि यदि व्यवसायों द्वारा निर्मित अनुचित लाभों को उनके चिह्नित प्राप्तकर्ता (जो उसको प्राप्त करने की पात्रता रखता हो) तक न पहुँचाया जा सके तो उसे उपर्युक्त कोष में जमा करा दिया जाए।**
- GST मुनाफाखोरी-रोधी नियमों के अनुसार, केंद्र और 'संबंधित राज्य' को दोषी व्यवसायों द्वारा उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करायी गयी राशि को समान रूप से साझा करने हेतु सशक्त बनाया गया है। 'सम्बन्धित राज्य' से तात्पर्य उस राज्य से होगा जहां मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण ने ऐसे व्यवसायों के विरुद्ध अपना आदेश पारित किया हो।
- वस्तु और सेवा कर (GST) के तहत गठित उपभोक्ता कल्याण कोष से प्राप्त आय, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ नियामक प्राधिकरणों को अनुदान के रूप में दी जा सकती है।

76.D

- **Statement 2 is correct:** Marginal Standing Facility (MSF) is a scheme announced by the Reserve Bank of India (RBI) in its Monetary Policy (2011-12) and refers to the penal rate at which banks can borrow money on an overnight basis from the central bank over and above what is available to them through the Liquidity Adjustment Facility window (repo and reverse repo).
- **Statement 1 is correct:** The interest rate for MSF borrowing was originally set at one per cent higher than the repo rate. RBI has lowered the difference between repo rate and MSF to 0.25%. For example, if the Repo rate is 6.0%, then the MSF rate is 6.25%. Both the MSF rate and Bank rate are equal.
- **Statement 3 is correct:** All Scheduled Commercial Banks having Current Account and Subsidiary General Ledger Account (SGL) with Reserve Bank, Mumbai will be eligible to participate in the MSF Scheme.
- **कथन 2 सही है:** सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति (2011-12) में घोषित एक योजना है। यह उस दंडात्मक दर (penal rate) को संदर्भित करती है, जिस पर बैंक केंद्रीय बैंक से तरलता समायोजन सुविधा (रेपो और रिवर्स रेपो) की सीमा से अतिरिक्त धन ओवरनाइट आधार पर (रात भर के लिए) उधार ले सकते हैं।
- **कथन 1 सही है:** MSF उधार के लिए ब्याज दर मूल रूप से रेपो दर से एक प्रतिशत अधिक निर्धारित की गई थी। RBI ने रेपो रेट और MSF के मध्य के अंतर को 0.25% तक कम कर दिया है। उदाहरण के लिए, यदि रेपो दर 6.0% है, तो MSF दर 6.25% होगी। MSF दर और बैंक दर दोनों समान हैं।
- **कथन 3 सही है:** रिजर्व बैंक (मुंबई) के साथ चालू खाता और सब्सिडियरी जनरल लेजर (SGL) खाता धारित करने वाले सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, MSF योजना में भाग लेने के लिए पात्र होते हैं।

77.C

- **Inflation redistributes wealth from creditors to debtors i.e. lenders suffer and borrowers benefit out of inflation.** The opposite effect takes place when inflation falls. Taxpayers suffer while paying their direct and indirect taxes. As indirect taxes are imposed on value, increased prices of goods make taxpayers pay increased indirect taxes. Similarly, due to inflation, the direct tax burden of the taxpayers also increases as tax payer's gross income moves to the upward slab of official tax brackets.

मुद्रास्फीति ऋणदाता से ऋण प्राप्तकर्ता की ओर धन का पुनर्वितरण करती है अर्थात मुद्रास्फीति से ऋणदाता को हानि होती है और ऋण प्राप्तकर्ता को लाभ होता है। मुद्रास्फीति की दर में कमी आने पर इसका विपरीत प्रभाव उत्पन्न होता है। करदाताओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के भुगतान के समय हानि उठानी पड़ती है। चूंकि अप्रत्यक्ष करों को मूल्य अथवा कीमतों पर आरोपित किया जाता है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करदाताओं को वर्द्धित अप्रत्यक्ष करों के भुगतान के लिए बाध्य करती है। इसी तरह मुद्रास्फीति के कारण करदाताओं पर प्रत्यक्ष कर के बोझ में भी वृद्धि होती है, क्योंकि करदाता की सकल आय आधिकारिक आयकर सीमा के ऊपर वाले स्लैब में प्रविष्ट हो जाती है।

78.A

- **Statement 1 is correct:** The SECC, 2011 has the following three objectives:
  - To enable households (both rural and urban) to be ranked based on their socioeconomic status. State Governments can then prepare a list of families living below the poverty line.
  - To make available authentic information that will enable caste-wise population enumeration of the country.
  - To make available authentic information regarding the socio-economic condition and education status of various castes and sections of the population.
- **Statement 2 is not correct:** It does not use the Tendulkar methodology for poverty estimation. The SECC measures deprivation along seven criteria - households with only one room with no solid walls and roof, those with no adult member aged 15-59, female-headed households with no adult male aged 15-59, those with differently abled members and no able-bodied member, SC/ST households, those with no literate member above the age of 25 and landless households deriving a major portion of their income from manual casual labour.
- **Statement 3 is not correct:** The data of SECC does not and cannot superimpose itself fully on the census data. While there is a high degree of compatibility in the two sets of data the findings could be different because the duration of the census and that of SECC is different. Census 2011, on the other hand, was conducted during the period 9th to 28th February 2011. Socio-Economic Caste Census 2011 was largely carried out in 2011 and 2012 with a few states taking enumeration and verification in 2013 also.
- **Statement 4 is not correct**: SECC-2011 is a study of the socio-economic status of rural and urban households and allows ranking of households based on predefined parameters. SECC 2011 has three census components which were conducted by three separate authorities but under the overall coordination of Department of Rural Development in the Government of India. Census in Rural Area has been conducted by the Department of Rural Development (DoRD). Census in Urban areas is under the administrative jurisdiction of the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (MoHUPA). Caste Census is under the administrative control of Ministry of Home Affairs: Registrar General of India (RGI) and Census Commissioner of India.
- **कथन 1 सही है:** SECC, 2011 के निम्नलिखित तीन उद्देश्य हैं:

o परिवारों (ग्रामीण और शहरी दोनों) को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान करना। इसके आधार पर राज्य सरकारें निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची तैयार कर सकती हैं।

o प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराना जो देश की जाति-वार जनगणना को सक्षम बनाएगी।

o विभिन्न जातियों और वर्गों के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति के संबंध में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराना।

- **कथन 2 सही नहीं है:** यह निर्धनता आकलन के लिए तेंदुलकर पद्धति का उपयोग नहीं करती है। SECC सात मानदंडों के आधार पर वंचनों का मापन करती है - पक्की दीवारों एवं छत रहित केवल एक कमरे वाले घर, वह परिवार जिनमें 15-59 आयु वर्ग के वयस्क सदस्य नहीं हैं, महिला मुखिया वाले वह परिवार जिनमें 15-59 आयु वर्ग के वयस्क पुरुष सदस्य नहीं हैं, दिव्यांग जनों वाले परिवार जहाँ कोई सक्षम सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वाले परिवार, वह परिवार जहाँ 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति साक्षर नहीं है तथा वे भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का एक बड़ा भाग अनियमित शारीरिक श्रम से प्राप्त करते हैं।
- **कथन 3 सही नहीं है:** SECC के आंकड़ों को जनगणना के आंकड़ों पर पूर्णतः अध्यारोपित (superimpose) नहीं किया जा सकता है। हालांकि आंकड़ों के दो समूहों में उच्च स्तरीय सुसंगतता व्याप्त है, लेकिन निष्कर्ष भिन्न प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि जनगणना और SECC की अवधि अलग-अलग है। 2011 की जनगणना 9 से 28 फरवरी 2011 की अवधि के दौरान आयोजित की गई। SECC 2011 को बड़े पैमाने पर वर्ष 2011 और 2012 में संपन्न किया गया, जिसमें कुछ राज्यों ने वर्ष 2013 में भी गणना और सत्यापन संबंधी कार्य संपन्न किए।
- **कथन 4 सही नहीं है:** SECC- 2011 ग्रामीण और शहरी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का एक अध्ययन है और पूर्व निर्धारित मापदंडों के आधार पर परिवारों को रैंक प्रदान करता है। SECC- 2011 में तीन जनगणना घटक हैं जो तीन अलग-अलग प्राधिकरणों द्वारा, लेकिन भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के समग्र समन्वय के अंतर्गत संचालित किए गए। ग्रामीण क्षेत्र में जनगणना ग्रामीण विकास विभाग (DoRD) द्वारा संपन्न की गई है। शहरी क्षेत्रों में जनगणना MoHUPA अर्थात आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (वर्तमान में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। जाति जनगणना, गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) और भारत के जनगणना आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

79.A
80.C
81.A
82.D
83.D
84.C

- The government of India is dependent on the supply of Phosphatic (P) and Potassic (K) fertilizers to the extent of 90% and 100% respectively on imports due to non-availability of indigenous raw materials within the country.
- **India has a few reserves of rock phosphate that too in limited quantity and of poor quality.** Therefore India imports diammonium phosphate (DAP) directly or produces it from imports of rock phosphate (phosrock) or phosphoric acid (phosacid). Indian DAP imports stood at around 4.3m tonnes in the previous fiscal year.

- **India is expected to keep importing 100% of its potash requirements, as it does not have domestic reserves of muriate of potash (MOP).** Potassium Chloride (commonly referred to as Muriate of Potash or MOP) is the most common potassium source used in agriculture, accounting for about 95% of all potash fertilizers used worldwide.
- India is trying to achieve self-sufficiency in Urea. Urea is produced using domestic gas, imported LNG and naphtha. **It is due to the limited availability of domestic Natural Gas production in the country that the Fertilizer units depend upon Regasified Liquefied Natural Gas.**
- भारत सरकार देश के भीतर स्वदेशी कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण फॉस्फेटिक (P) और पोटाशिक (K) उर्वरकों की आपूर्ति हेतु क्रमशः 90% और 100% तक आयात पर निर्भर है।
- **भारत में रॉक फॉस्फेट के कुछ भंडार विद्यमान हैं जिनकी मात्रा सीमित है तथा गुणवत्ता निम्न है।** इसलिए भारत डाइअमोनियम फॉस्फेट (DAP) का प्रत्यक्ष रूप में आयात करता है या आयातित रॉक फॉस्फेट (phosrock) अथवा फॉस्फोरिक एसिड (phosacid) से इसका उत्पादन करता है। पिछले राजकोषीय वर्ष में भारत द्वारा लगभग 4.3 टन DAP का आयात किया गया था।
- **भारत को अपनी 100% पोटाश आवश्यकताओं की पूर्ति आयात के माध्यम से करनी होती है, क्योंकि भारत में म्यूरेट ऑफ़ पोटाश (MOP) के घरेलू भंडार विद्यमान नहीं हैं।** पोटैशियम क्लोराइड (जिसे सामान्यतः MOP के रूप में जाना जाता है) कृषि में उपयोग किए जाने वाले पोटैशियम का सबसे सामान्य स्रोत है। MOP विश्व भर में उपयोग किए जाने वाले सभी पोटाश उर्वरकों का लगभग 95% है।
- भारत यूरिया में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। यूरिया का उत्पादन घरेलू गैस, आयातित LNG और नेफ्था के उपयोग से किया जा रहा है। **देश में घरेलू स्तर पर प्राकृतिक गैस के उत्पादन की सीमित उपलब्धता के कारण उर्वरक इकाइयां रिगैसीफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (Regasified Liquefied Natural Gas) पर निर्भर हैं।**

85.A

- **Statement 1 is correct:** GFCF measures the value of acquisitions of new or existing fixed assets by the business sector, governments and "pure" households (excluding their unincorporated enterprises) less disposals of fixed assets. GFCF is a component of the expenditure on the gross domestic product (GDP), and thus shows something about how much of the new value added in the economy is invested rather than consumed. One of the reasons for low GFCF is due to low spending by the private sector in the capital asset. The growth of the productive capacity of the economy of the State depends on its rate of capital accumulation and it is assessed by estimating the Capital Formation of that State. The higher the rate of growth of Capital Formation, higher would be the productive capacity of the economy, whereas its paucity leads to the low level of production with higher cost. Thus Capital Formation serves as a very important indicator in measuring the magnitude of growth of productive potential of the economy.
- **Statement 2 is correct:** FDI can be used to finance fixed capital formation thus improving the GFCF.
- **Statement 3 is not correct:** According to the Economic Survey 2017-18, GFCF has declined in the past couple of years. The gross fixed capital formation climbed from 26.5% in 2003 to a peak of 35.6% in 2007 and then fell to 26.4% in 2017. However, according to the recent Financial stability report by the RBI, GFCF figures have improved in the last quarter of 2018.
- **कथन 1 सही है:** सकल स्थायी पूंजी निर्माण (Gross fixed capital formation: GFCF) का मापन व्यवसाय क्षेत्र, सरकारों और "शुद्ध" परिवारों (उनके गैर-निगमित उद्यमों को छोड़कर) द्वारा नवीन या मौजूदा स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में से स्थायी परिसंपत्तियों के विक्रय को घटा कर किया जाता है। GFCF सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर व्यय का एक घटक है और इस प्रकार इससे ज्ञात होता है कि अर्थव्यवस्था में जोड़े गए नवीन मूल्य में से कितने भाग का उपभोग के बजाय निवेश किया गया है। निम्न GFCF के कारणों में से एक निजी क्षेत्र द्वारा पूंजीगत परिसंपत्ति में कम व्यय किया जाना है। राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता की संवृद्धि उसकी पूंजी संचय की दर पर निर्भर करती है और इसका आकलन उस राज्य के पूंजी निर्माण से होता है। पूंजी निर्माण की वृद्धि दर जितनी अधिक होगी, अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता उतनी ही अधिक होगी, जबकि इसमें कमी होने से उच्च लागत के साथ निम्न उत्पादन प्राप्त होता है। इस प्रकार पूंजी निर्माण अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता के विकास के परिमाण को मापने में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में कार्य करता है।
- **कथन 2 सही है**: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश **(**FDI) का उपयोग स्थायी पूंजी निर्माण के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप GFCF में सुधार होता है।
- **कथन 3 सही नहीं है**: आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, विगत कुछ वर्षों में GFCF में गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2003 में GFCF 26.5% से बढ़कर 2007 में 35.6% हो गया था और 2017 में यह पुनः गिरकर 26.4% के स्तर पर आ गया। हालांकि RBI द्वारा हाल ही में जारी की गयी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, 2018 की अंतिम तिमाही में GFCF में सुधार दर्ज किया गया है।

86.D

- RBI has issued a policy action guideline (first in December 2002 and revised in 2014 and 2017) in the form of Prompt Corrective Action (PCA) Framework if a commercial bank's financial condition worsens below a mark.
- The PCA framework specifies the trigger points or the level in which the RBI will intervene with corrective action. These trigger points are expressed in terms of parameters for the banks. It has three risk threshold levels (1 being the lowest and 3 the highest) based on where a bank stands on these parameters. The parameters that invite corrective action from the central bank are:
  - **Capital Adequacy Ratio (CAR)** - is also known as Capital to Risk (Weighted)Assets Ratio (CRAR), is the ratio of a bank's capital to its risk. There are different types of risks in a bank such as credit risk, Market risk, Liquidity risk, operational risk etc. Banks with a capital

to risk-weighted assets ratio (CRAR) of less than 10.25 per cent but more than 7.75 per cent fall under threshold 1. Those with CRAR of more than 6.25 per cent but less than 7.75 per cent fall in the second threshold. In case a bank's common equity Tier 1 (the bare minimum capital under CRAR) falls below 3.625 per cent, it gets categorised under the third threshold level

- **Asset Quality (**Net Non-Performing Assets (NPA))- Banks that have a net NPA of 6 per cent or more but less than 9 per cent fall under threshold 1, and those with 12 per cent or more fall under the third threshold level.
- **Profitability (Return on Assets)**- Banks with a negative return on assets for two, three and four consecutive years fall under threshold 1, threshold 2 and threshold 3, respectively.
- **Leverage** - The Tier 1 leverage ratio. It is the relationship between a banking organization's core capital and its total assets. The Tier 1 leverage ratio is calculated by dividing Tier 1 capital by a bank's average total consolidated assets and certain off-balance sheet exposures. Tier 1 capital consists of shareholders' equity and retained earnings.

- जब किसी भी वाणिज्यिक बैंक की वित्तीय स्थिति एक निश्चित मानक से अधिक ख़राब हो जाती है, तब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा नीतिगत कार्रवाई दिशा-निर्देश (सर्वप्रथम दिसंबर 2002 में जारी तथा 2014 और 2017 में संशोधित) को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action: PCA) के ढाँचे के रूप में जारी किया जाता है।
- PCA ढांचा उन ट्रिगर बिंदुओं या उस स्तर को निर्दिष्ट करता है जिसमें RBI सुधारात्मक कार्रवाई के माध्यम से हस्तक्षेप कर सकता है। ये ट्रिगर बिंदु बैंकों के लिए कुछ निश्चित मापदंडों के संदर्भ में व्यक्त किए जाते हैं। इसमें तीन रिस्क थ्रेशोल्ड स्तर होते हैं (जिनमें 1 सबसे कम तथा 3 सर्वाधिक होता है) जो इन मापदंडों पर किसी बैंक की स्थिति पर आधारित होते हैं। वे मापदंड जिनके आधार पर केंद्रीय बैंक सुधारात्मक कार्रवाई करता है, निम्नलिखित हैं:

o **पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio: CAR)** को जोखिम-भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (CRAR) के रूप में भी जाना जाता है। यह अनुपात बैंक की पूंजी और इसके जोखिम के अनुपात को इंगित करता है। बैंक में विभिन्न प्रकार के जोखिम विद्यमान होते हैं, यथा- क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम, परिचालन जोखिम आदि। जिन बैंकों के पास पूंजी, CRAR के रूप में 10.25 प्रतिशत से कम परंतु 7.75 प्रतिशत से अधिक मौजूद होती है, वे थ्रेशहोल्ड 1 के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। जिनका CRAR 6.25 प्रतिशत से अधिक परन्तु 7.75 प्रतिशत से कम होता है, वे थ्रेशहोल्ड 2 के अंतर्गत आते हैं। यदि किसी बैंक की टियर 1 के रूप में सामान्य इक्विटी (CRAR के तहत अल्प न्यूनतम पूंजी) 3.625 प्रतिशत से कम हो जाती है, तो इसे थ्रेशहोल्ड 3 स्तर में शामिल किया जाता है।

o **परिसंपत्ति गुणवत्ता {निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs)}:** जिन बैंकों का निवल NPA 6 प्रतिशत या उससे अधिक परंतु 9 प्रतिशत से कम है, उन्हें थ्रेशहोल्ड 1 के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है तथा 12 प्रतिशत या उससे अधिक NPA वाले बैंकों को थ्रेशहोल्ड 3 में शामिल किया जाता है।

o **लाभप्रदता (परिसम्पत्तियों पर रिटर्न):** वे बैंक जिन्हें निरंतर दो, तीन एवं चार वर्षों से परिसंपत्तियों पर नकारात्मक रिटर्न प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें क्रमशः थ्रेशहोल्ड 1, थ्रेशहोल्ड 2 तथा थ्रेशहोल्ड 3 के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

o **लीवरेज (Leverage):** यह टीयर 1 लीवरेज अनुपात को संदर्भित करता है। यह एक बैंकिंग संगठन की मुख्य पूंजी (कोर कैपिटल) तथा इसकी कुल परिसंपत्तियों के मध्य का संबंध है। टीयर 1 लीवरेज अनुपात की गणना टीयर 1 पूंजी को बैंक की कुल औसत समेकित परिसंपत्तियों एवं तुलन पत्र से अतिरिक्त कुछ जोखिमों से विभाजित करके की जाती है। टियर 1 पूंजी के अंतर्गत शेयरधारकों की इक्विटी तथा प्रतिधारित उपार्जन (retained earnings) सम्मिलित होते हैं।

87.C

- **Statements 1 and 2 are correct:** WTO's Special Safeguard Mechanism (SSM) is a protection measure **allowed for developing countries** to take contingency restrictions **against agricultural imports** that are causing injuries to domestic farmers. The contingency measure is **the imposition of tariff** if the import surge causes welfare loss to the domestic poor farmers.
- The developing countries were given the concession to adopt a Special Safeguard Mechanism (SSM) besides the existing safeguards (like the Special Agricultural Safeguard or the SSG) at the Doha Ministerial Conference.
- **Statement 3 is not correct:** The SSG was available to all countries- both developing and developed whereas the SSM is allowed only to the developing countries. It is to be mentioned that the SSG was available as it was inducted under the GATT agreement; whereas the SSM was the invention of the Doha Ministerial Conference.

- **कथन 1 और 2 दोनों सही हैं:** विश्व व्यापार संगठन (WTO) का विशेष रक्षोपाय तंत्र (Special Safeguard Mechanism: SSM) वस्तुतः **विकासशील देशों को प्रदत्त** एक संरक्षण उपाय है, ताकि वे घरेलू किसानों को क्षति पहुँचाने वाले **कृषि आयातों के विरुद्ध आकस्मिक प्रतिबंधों** को आरोपित कर सकें। यदि आयात में आकस्मिक वृद्धि के कारण घरेलू निर्धन किसानों को क्षति पहुँचती है, तो आकस्मिक उपाय के रूप में आयात पर प्रशुल्क आरोपित किया जा सकता है।
- दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में विकासशील देशों को SSM के अतिरिक्त मौजूदा सुरक्षा उपायों (जैसे- विशेष कृषि सुरक्षा या SSG) को अपनाने के लिए छूट प्रदान की गई थी।
- **कथन 3 सही नहीं है:** जहाँ SSG सभी देशों (अर्थात् विकासशील तथा विकसित दोनों) के लिए उपलब्ध है, वहीं SSM केवल विकासशील देशों के लिए उपलब्ध है। ध्यातव्य है कि SSG को GATT समझौते के अंतर्गत शामिल किया गया था; जबकि SSM को दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।

88.B

- Capital gain is a rise in the value of a capital asset (investment or real estate) that gives it a higher worth than the purchase price. The gain is not realized until the asset is sold and that too at a profit.
- Income from Capital Gains is one of the five heads of income, taxable under the Income Tax Act, 1961. Capital gain is concerned with the transfer of capital asset.

- Capital gains arise whenever a capital asset is transferred (by way of sale or otherwise) by the assessee. They are further classified into two: short-term capital gains (STCG) and long-term capital gains (LTCG) on the basis of the holding period of the asset
- **What is a capital asset?**
  - **Any property (land, house etc)** whether or not connected with the business or profession of the assessee is a capital asset. Additionally, securities held by FII (Foreign Institutional Investor) according to SEBI Regulations are capital assets.
  - **Hence the house sold at a profit after 5 years will attract capital gains tax while equity sold at a loss will not attract capital gains tax.**
- The **capital asset doesn't include the following**:
  - Stock-in-trade (the goods kept in hand by a business for the purposes of its trade)
  - **Agricultural land in India.**
  - Personal effects which can be moved such as furniture used by the assessee or family, utensils, etc.
    - The following are not included in personal effects- jewellery, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures or any work of art.
  - Central Government 7% Gold Bonds & 6.5% bonds;
  - Central Government's Bearer Bonds; and
  - Gold Deposit Bonds under Gold Deposit Scheme, 1999.
- पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) पूंजीगत परिसम्पत्तियों (निवेश या रियल एस्टेट) के मूल्य में उस वृद्धि को संदर्भित करता है जो इसे खरीद मूल्य से उच्च कीमत प्रदान करती है। यह लाभ तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि किसी परिसम्पत्ति का मुनाफे पर विक्रय न किया गया हो।
- पूंजीगत लाभ से प्राप्त आय, आय के पांच प्रमुख स्रोतों में से एक है तथा आयकर अधिनियम,1961 के तहत कर-योग्य है।
- पूंजीगत लाभ तब प्राप्त होता है जब किसी पूंजीगत परिसम्पत्ति का उसके धारक द्वारा हस्तांतरण (विक्रय के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से) किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्ति की धारण अवधि के आधार पर इसे आगे अन्य दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: अल्पावधिक पूंजीगत लाभ (STCG) और दीर्घावधिक पूंजीगत लाभ (LTCG)।
- **पूंजीगत सम्पत्ति क्या होती है?**

o **परिसम्पत्ति धारक की कोई भी सम्पत्ति (भूमि, मकान आदि)** चाहे वह उसके व्यवसाय या वृत्ति से संबंधित हो अथवा नहीं, एक पूंजीगत परिसंपत्ति होती है। इसके अतिरिक्त, सेबी (SEBI) के विनियमों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा धारित प्रतिभूतियां भी पूंजीगत परिसम्पत्तियां होती हैं।

o **इस प्रकार पांच वर्षों के पश्चात् लाभ पर बेचा गया एक मकान पूंजीगत लाभ कर के अधीन होगा जबकि हानि पर बेचे गए इक्विटी शेयर पूंजीगत लाभ कर के अधीन नहीं होंगे।**

- **पूंजीगत परिसंपत्ति में निम्नलिखित शामिल नहीं होते हैं:**

o स्टॉक-इन-ट्रेड (किसी व्यवसाय द्वारा व्यापार हेतु संगृहीत वस्तुएं)

o **भारत में कृषि भूमि।**

o निजी सम्पत्ति जिसे हस्तांतरित किया जा सकता हो, जैसे परिसंपत्ति धारक या परिवार द्वारा प्रयुक्त फर्नीचर, घरेलू सामान आदि।

- निजी सम्पत्ति में अग्रलिखित वस्तुएं शामिल नहीं होतीं हैं- आभूषण, पुरातात्विक संग्रहण, चित्र, प्रतिमाएं या कोई अन्य कलाकृति।

o केंद्र सरकार के 7% स्वर्ण बॉण्ड्स और 6.5% बॉण्ड्स।

o केंद्र सरकार के धारक बॉण्ड्स (Bearer Bonds) तथा

o स्वर्ण जमा योजना,1999 के तहत गोल्ड डिपॉजिट बॉण्ड्स।

89.A

Statement 1 is correct and statement 2 is not correct: Total FDI inflows have been increasing constantly with 16,054 million US $ in 2013-14 to 37,366 million US $ in 2017-18. Maximum FDI has been received from Mauritius

- **Statement 3 is not correct:** Manufacturing has received maximum FDI in the last five years.

कथन 1 सही है परन्तु कथन 2 सही नहीं है: कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) अंतर्वाह में वर्ष 2013-14 के 16,054 मिलियन डॉलर के स्तर से वर्ष 2017-18 में 37,366 मिलियन डॉलर तक निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। अधिकतम FDI मॉरिशस से प्राप्त किया गया है।

- **कथन 3 सही नहीं है:** विगत पांच वर्षों में अधिकतम FDI विनिर्माण क्षेत्रक द्वारा प्राप्त किया गया। है।

90.B

- As per the RBI guidelines **"A Non-Banking Financial Company (NBFC) is a company registered under the Companies Act, 1956 engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares/stocks/bonds/debentures/securities issued by Government or local authority."**
- Section 45-IB of RBI Act requires NBFCs to compulsorily maintain liquid assets to the tune of 15% of accepted deposits, wherein 10% thereof should be in the nature of approved securities. NBFCs lend and make investments and hence their activities are akin to that of banks; however, there are a few differences as given below:

i. **NBFC cannot accept demand deposits;**

ii. NBFCs do not form part of the payment and settlement system and cannot issue cheques drawn on itself;

iii. Deposit insurance facility of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation is not available to depositors of NBFCs, unlike in case of banks.

- **Hence statements 2 and 3 are not correct.**
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार **"एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) वह कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है तथा ऋण एवं अग्रिम धनराशि प्रदान करने के व्यवसाय और सरकार व स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी शेयर/स्टॉक्स/बॉण्ड्स/ऋणपत्रों/प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में संलग्न है।"**

- RBI अधिनियम के सेक्शन 45-IB के तहत NBFCs को स्वीकृत जमाओं के 15% तक तरल परिसंपत्तियाँ बनाए रखना अनिवार्य है, जिसमें से 10% अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में होना चाहिए। NBFCs ऋण प्रदान कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार उनकी गतिविधियाँ बैंकों के समान प्रकृति की होती हैं, परन्तु इनके मध्य निम्नलिखित कुछ विभेद विद्यमान हैं:
  - **NBFCs मांग जमाओं को स्वीकार नहीं कर सकते।**
  - **NBFCs भुगतान और निपटान प्रणाली का भाग नहीं होते तथा स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकते।**
  - बैंकों के विपरीत, NBFCs के जमाकर्ताओं हेतु निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) की जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं होती।
- **इसलिए कथन 2 और 3 सही नहीं है।**

91. D

92.C

- **A convertible note is an instrument issued by a start-up company evidencing receipt of money initially as debt**, which is repayable at the option of the holder, or which is convertible into such number of equity shares of such startup company, within a period not exceeding five years from the date of issue of the convertible note, upon occurrence of specified events as per the other terms and conditions agreed to and indicated in the instrument.
- A person resident outside India (other than an individual who is a citizen of Pakistan or Bangladesh or an entity which is registered/ incorporated in Pakistan or Bangladesh), may purchase convertible notes issued by an Indian start-up company for an amount of twenty-five lakh rupees or more in a single tranche. A start-up company engaged in a sector where foreign investment requires Government approval may issue convertible notes to a non-resident only with the approval of the Government.
- एक 'परिवर्तनीय नोट' वस्तुतः एक स्टार्ट-अप कंपनी द्वारा आरंभ में ही ऋण के तौर पर प्राप्त धन (पूँजी) हेतु साक्ष्य के रूप में जारी एक लिखत (इंस्ट्रूमेंट) होता है, जो उसके धारक को उसके ऑप्शन के आधार पर पुनर्भुगतान के योग्य होता है अथवा इस नोट को जारी करने की तारीख से पाँच वर्षों से अनधिक अवधि के भीतर उस संख्या में उस स्टार्ट-अप कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय होने हेतु अर्ह होता है। यह उक्त लिखत में उल्लिखित और स्वीकार किए गए नियमों और शर्तों के अनुरूप विशिष्ट स्थितियों में परिवर्तनीय होता है।
- भारत के बाहर निवास करने वाला व्यक्ति (पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक अथवा पाकिस्तान या बांग्लादेश में पंजीकृत/गठित संस्था के अतिरिक्त), एकमुश्त रूप से किसी भारतीय स्टार्ट-अप कंपनी द्वारा जारी पच्चीस लाख रुपये या उससे अधिक के परिवर्तनीय नोट खरीद सकता है। एक स्टार्ट-अप कंपनी जो एक ऐसे क्षेत्र में संलग्न है जहाँ विदेशी निवेश के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है, केवल सरकार की अनुमति के पश्चात् ही किसी अनिवासी (non-resident) को परिवर्तनीय नोट जारी कर सकती है।

93.C

- World Bank published the following reports:
  - Global Economic Prospects: According to 2019 report, India's GDP is expected to grow at 7.3 per cent in the fiscal year 2018-19, and 7.5 per cent in the following two years.
  - World Development Report
  - Doing Business report: India leapfrogged to the 77th rank in the World Bank's latest Ease of Doing Business rankings jumping 23 notches from last year.
- World Economic Outlook & Global Financial Stability Report are published by the International Monetary Fund.
- विश्व बैंक द्वारा निम्नलिखित रिपोर्टों का प्रकाशन किया जाता है :
  - **ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट (Global Economic Prospects):** वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2018-19 में 7.3 प्रतिशत तथा अगले दो वर्षों में 7.5 प्रतिशत रहने की अपेक्षा है।
  - विश्व विकास रिपोर्ट (World Development Report)
  - **डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट (Doing Buisness Report):** भारत ने विश्व बैंक की नवीनतम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में 23 रैंक का सुधार करते हुए हुए 77वां स्थान प्राप्त किया है।
- **वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक** और **ग्लोबल फाइनेंसियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट)** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा प्रकाशित की जाती हैं।

94.A

- A 'stimulus' is an attempt by policymakers to kickstart a sluggish economy through a package of measures. It may be given in two forms:
  - **Monetary stimulus**: It will see the central bank expanding money supply or **reducing the cost of money (interest rates)**, to spur consumer spending. Hence **reducing the repo rates is a monetary stimulus**, not a fiscal stimulus.
  - **Fiscal stimulus**: It either entails the higher government spending or putting more money in the hands of consumers. It may be in form of **slashing tax rates**, **, hiking the salaries of government employees on the recommendation of various pay commission etc**
- There are different perspectives on the utility of such packages. However, it proved beneficial for the Indian economy during 2008-09.
- **India's fiscal stimulus package in 2008-09 included** a blanket 4 percentage point cut in the excise duty rates, ₹20,000 crore in plan spending by the Government, ₹10,000 crore **funding for infrastructure finance**, export subsidies and a large government order for new buses to replace State public transport fleets. All this, on top of pay revisions for government employees, did prove hugely successful at revving up the economy.

- 'प्रोत्साहन', नीति निर्माताओं द्वारा उपायों के एक पैकेज के माध्यम से मंद अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने का एक प्रयास होता है। यह दो रूपों में प्रदान किया जा सकता है:

o **मौद्रिक प्रोत्साहन:** इसके अंतर्गत उपभोक्ता व्यय में वृद्धि करने के लिए, केन्द्रीय बैंक द्वारा या तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि की जाती है अथवा मुद्रा की लागत (ब्याज दरों) को कम किया जाता है। इसलिए **रेपो दरों को कम करना** एक मौद्रिक प्रोत्साहन है, न कि राजकोषीय प्रोत्साहन।

o **राजकोषीय प्रोत्साहन:** इसके अंतर्गत या तो सरकारी व्यय में वृद्धि की जाती है अथवा उपभोक्ताओं के पास अधिक मुद्रा होने की व्यवस्था की जाती है। यह **कर की दरों में कमी**, विभिन्न वेतन आयोगों की अनुशंसाओं पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने आदि के रूप में हो सकता है।

- ऐसे पैकेजों की उपयोगिता पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण विद्यमान हैं। हालांकि यह वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक साबित हुआ था।
- **वर्ष 2008-09 में भारत के राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज में** उत्पाद शुल्क की दरों में 4 प्रतिशत की कटौती, सरकार द्वारा 20,000 करोड़ का योजना व्यय, **अवसंरचना वित्तपोषण के लिए** 10,000 करोड़ की धनराशि, निर्यात सब्सिडी तथा राज्य परिवहन बेड़े हेतु नई बसों के प्रतिस्थापन लिए एक व्यापक सरकारी आदेश शामिल था। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन के साथ उपर्युक्त सभी उपाय अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने में अत्यधिक सफल सिद्ध हुए थे।

95.C

- GDP is the single number of the total monetary value of all the finished goods and services produced within a country's borders (domestically) during a particular time period (quarterly/annually).
- GNP is the aggregate market value of all goods and services produced by all of its citizens and businesses irrespective of their location (local or global) during a particular period. Essentially, GNP acts as a superset of GDP, as it factors in the net income from abroad in addition to the GDP.
- GNP = GDP + (Net income earned by domestic residents/businesses from overseas investments) – (Net income earned by foreign residents/businesses from domestic investments).
- So, GDP is based on location, while GNP is based on citizenship.
- **Statement 1 is not correct**: Whether GDP is higher than GNP depends on the relative performance of citizens of different countries living outside their native countries. Higher GNP than GDP indicates that citizens of a country are doing better abroad and vice versa.
- **Statement 2 is correct**: Net National Product (NNP) at factor cost is also called national income. NNP is derived by subtracting depreciation allowance from GNP.
- **Statement 3 is not correct:** Gross value added (GVA) is defined as the value of output less the value of intermediate consumption. Value added represents the contribution of labor and capital to the production process.
  - When the value of taxes on products (less subsidies on products) is added, the sum of value added for all resident units gives the value of the gross domestic product (GDP). Thus, **Gross Domestic Product (GDP)** of any nation represents the sum total of the gross value added (GVA) (i.e, without discounting for capital consumption or depreciation) in all the sectors of that economy during the said year after **adjusting for taxes and subsidies.**
- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी विशेष समयावधि (त्रैमासिक/वार्षिक) के दौरान किसी देश की सीमा के अंदर (घरेलू रूप से) उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के लिए निर्धारित एक एकल संख्या है।
- सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) किसी विशेष अवधि के दौरान स्थान विशेष पर ध्यान दिए बिना (स्थानीय अथवा वैश्विक) किसी देश के सभी नागरिकों और व्यवसायों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है। वस्तुतः GNP, GDP के अधिसमुच्चय (superset) के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसमें GDP के अतिरिक्त विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी शामिल किया जाता है।
- GNP = GDP + (घरेलू निवासियों/व्यवसायों द्वारा विदेश में निवेश से अर्जित निवल आय) - (विदेशी निवासियों/व्यवसायों द्वारा संदर्भित देश में निवेश से अर्जित निवल आय)।
- इस प्रकार, GDP स्थान विशेष पर आधारित है जबकि GNP नागरिकता पर आधारित है।
- **कथन 1 सही नहीं है:** GNP की तुलना में GDP अधिक है या नहीं यह मूल देशों के बाहर निवास करने वाले विभिन्न देशों के नागरिकों के सापेक्ष प्रदर्शन पर निर्भर करता है। GDP की तुलना में उच्च GNP यह इंगित करता है कि किसी देश के नागरिक विदेशों में बेहतर कार्य कर रहे हैं, इसके विपरीत GDP की तुलना में निम्न GNP का अर्थ है कि देश के नागरिक विदेशों में बेहतर कार्य नहीं कर रहे हैं।
- **कथन 2 सही है:** कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। NNP को GNP में से मूल्यह्रास भत्ता घटाकर प्राप्त किया जाता है।
- **कथन 3 सही नहीं है:** सकल मूल्य वर्धन (GVA) निर्गत (आउटपुट) के मूल्य से मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य को घटाकर प्राप्त किया जाता है। मूल्य वर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम और पूंजी के योगदान को प्रदर्शित करता है।

o जब सभी घरेलू इकाइयों के सकल मूल्य वर्धन में उत्पादों पर करों का मूल्य (उत्पादों पर सब्सिडी को घटाकर) जोड़ा जाता है तो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का मान प्राप्त होता है। इस प्रकार किसी वर्ष के दौरान किसी राष्ट्र का **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** उसकी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कर और सब्सिडी के समायोजन के पश्चात सकल मूल्य वर्धन (GVA) की कुल राशि (अर्थात् पूंजी उपभोग या मूल्यह्रास के बिना) का प्रतिनिधित्व करता है।

96.C

Recession

• Recession is a slowdown or a massive contraction in economic activities. A significant fall in spending generally leads to a recession.

• Such a slowdown in economic activities may last for some quarters thereby completely hampering the growth of an economy. In such a situation, economic indicators such as GDP, corporate profits, employments, etc., fall.

• This creates a mess in the entire economy. To tackle the menace, economies generally react by loosening their monetary policies by infusing more money into the system, i.e., by increasing the money supply.

• This is done by reducing the interest rates. Increased spending by the government and decreased taxation are also considered good answers for this problem. The recession which hit the globe in 2008 is the most recent example of a recession.

मंदी

• मंदी आर्थिक गतिविधियों में बड़े पैमाने पर संकुचन है। व्यय में गिरावट आम तौर पर मंदी की ओर ले जाती है।

• आर्थिक गतिविधियों में इस तरह की मंदी कुछ तिमाहियों तक बनी रह सकती है, ऐसी स्थिति में, अर्थव्यवस्था की वृद्धि में बाधा आती है। आर्थिक संकेतक जैसे कि जीडीपी, कॉरपोरेट प्रॉफिट, एंप्लॉयमेंट आदि में गिरावट आती हैं।

• यह पूरी अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करता है। आम तौर पर खतरे से निपटने के लिए, अर्थव्यवस्थाएं
सिस्टम में अधिक धन (पैसे की आपूर्ति बढ़ाकर) अथवा अपनी मौद्रिक नीतियों को सरल कर देती हैं।

• ऐसे समय ब्याज दरों को कम करके किया जाता है। सरकार द्वारा खर्च में वृद्धि और कम कराधान को भी इस समस्या के लिए अच्छा उपाय माना जाता है। मंदी जो 2008 में वैश्विक रूप में उभरी थी, मंदी का सबसे ताजा उदाहरण है।

97.A

98.C

99.C

100.C